राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष 37 ▪ अंक 5 ▪ नवम्बर 2016 ▪ ₹10 ▪ पृष्ठ 36

सर्जिकल स्ट्राइक

साहस और संकल्प की मिसाल

वामपंथी कुचक्र में फँसा जेएनयू और नजीब

रानी लक्ष्मीबाई

तलाक तलाक तलाक

परिषद्-गतिविधियाँ

भोपाल में अभाविप की दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते
अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय बिदरे

पूर्वोत्तर में हुए छात्र संघ चुनाव में
अभाविप की विजय

केरल में हुए छात्र संघ चुनाव में
अभाविप की विजय

राष्ट्रीय
छात्रशक्ति

शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका

वर्ष 37, अंक 5
नवम्बर 2016

संपादक-मण्डल :
आशुतोष
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन

संपादकीय पत्राचार :
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
छात्रशक्ति भवन, 26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002; फोन : 011-23216298
वेबसाइट : www.abvp.org

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/chhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के लिए राजकुमार शर्मा द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नयी दिल्ली-110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ.आई.ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नयी दिल्ली-110092 से मुद्रित।

इस अंक में...

4 संपादकीय
6 सर्जिकल स्ट्राइक : साहस और संकल्प की मिसाल
10 सारंडा के जंगल में गूँजा वन्दे मातरम्...
11 केरल में अभाविप ने लहराया जीत का परचम
12 पूर्वोत्तर में अभाविप की शानदार जीत
13 वर्तमान शिक्षा-नीति में बदलाव की जरूरत : साकेत बहुगुणा
14 भोपाल में अभाविप की दो-दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला संपन्न
15 वामपंथी कुचक्र में फँसा जेएनयू और नजीब
18 नीतीश सरकार का दलित-विरोधी चेहरा उजागर हुआ : विनय बिदरे
20 संघ लोकसेवा आयोग के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन
21 रानी लक्ष्मीबाई : महिला सशक्तीकरण की प्रेरणा
23 राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम : जी. लक्ष्मण
23 इन्दौर में होगा अभाविप का 62वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन
24 मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें ए.एम.यू. उपाध्यक्ष : डॉ. प्रभाकर रॉय
25 लक्ष्य के आगे गायब हो जाती हैं अड़चनें : एम.पी. गोयल
26 ऐसे थे अपने दीनदयाल जी
28 तीन तलाक : मुस्लिम महिला पर कहर
31 परिचर्चा : पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम देने का औचित्य ?
34 हुंकार रैली से छात्रों की ताकत का एहसास कराएगी विद्यार्थी परिषद्

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

यह अंक जब आपके हाथों में पहुँचने की तैयारी में है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं। एक, भारत में पाँच सौ और एक हज़ार के नोटों के प्रचलन को रोक कर नये नोट जारी करने की घोषणा हुई है वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें शुरूआत में कम गंभीरता के साथ लिया जा रहा था, निर्णायक जीत की ओर बढ़ गए हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि राष्ट्रीय हित की लड़ाई में वे दुस्साहसिक फ़ैसले ले सकते हैं। काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था ने जहाँ विकास को भीतर से ही खाना शुरू कर दिया था वहीं नकली भारतीय मुद्रा के बल पर पाकिस्तानी खुफिया एज़ेन्सी आईएसआई भारत में अराजकता को बनाए रखने में कामयाब हो रही थी।

भारत सरकार के इस निर्णय से शुरूआती कठिनाइयों से तो इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन भारतीय अर्थव्यस्था पर होनेवाले सुपरिणाम के मुकाबले यह कुछ भी नहीं। निश्चित तौर पर जहाँ बड़ी मात्रा में काला धन बाहर आने की उम्मीद जगी है वहीं आतंकवाद को खाद-पानी पहुँचाने में लगी भारतविरोधी ताकतों की कुछ समय के लिये ही सही, कमर टूट जायेगी।

काले धन के खिलाड़ियों को चौंकाते हुए प्रधानमंत्री ने बड़े नोटों पर रोक की अप्रत्याशित घोषणा की। संभलने का अवसर दिये बिना जहाँ उन्हें सारी काली कमाई को उजागर करने के लिए विवश किया वहीं गरीब आदमी की देशभक्ति और ईमानदारी की दुहाई भी दी। यद्यपि जनधन योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों तक खाते खोलने की सुविधा और डेबिट कार्ड के प्रचलन के बाद जब स्वेच्छा से काली कमाई की घोषणा का अवसर दिया गया था तो यह संकेत मिल ही रहा था कि इन अवसरों को चूकनेवाले लोगों को बड़ी चोट लगने जा रही है। शायद उन लोगों को अब सचमुच सोचने का मौका है जो इन संकेतों को पढ़ने में असफल रहे अथवा जिन्हें अपनी पहुंच और प्रबंधन का गुमान था।

दूसरी घटना हुई सुदूर अमेरिका में, जहाँ पूर्वानुमानों को ध्वस्त करते हुए राजनीति में नया कदम रखनेवाले डोनाल्ड ट्रंप ने भरपूर अनुभव रखनेवाली हिलेरी क्लिंटन को धूल चटायी। अमेरिका में ट्रंप का राजनैतिक उभार प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में अवतरण से मिलता-जुलता है। इस साम्यता की चर्चा तो होगी ही।

भारत और अमेरिका, दोनों चुनावों को एक साथ रखकर विश्लेषण करें तो कुछ निष्कर्षों तक पहुँचा जा सकता है। पहला, लोकतांत्रिक विश्व में अब राजनैतिक आकांक्षाओं ने वैश्विक रूप ले लिया है और दुनिया के हर लोकतंत्र में परिवारों की प्रधानता को चुनौती मिल रही है। अपने दम पर आगे बढ़ने और राष्ट्रीय हित में कठोर फैसले लेनेवाले राजनेताओं को जनता आगे आने का अवसर दे रही है। दूसरा, राष्ट्रवाद की बयार एक बार फिर बह निकली है और तरह-तरह के नारों की आड़ में राष्ट्रीय हितों से समझौते करनेवाले और विचारारा

लादनेवाले व्यक्तियों और दलों को साफ़ तौर पर नकारा जा रहा है।

तीसरा, पाकिस्तान और चीन को लेकर भारत की चिन्ताओं पर ट्रंप सकारात्मक प्रतिक्रिया जताते रहे हैं। यह ट्रंप के साथ-साथ भारतीय कूटनीतिक ढाँचे की भी परीक्षा होगी कि आनेवाले समय में विश्व व्यवस्था में भारतीय अवस्थिति हमारे अनुकूल रहे। इसका सीधा पैमाना है कि अमेरिका पाकिस्तान को दी जानेवाली सहायता पर अंकुश लगाये, पाक व चीन अधिक्रांत जम्मू-काश्मीर तथा हिंद महासागर में भारतीय हितों का समर्थन करे और सुरक्षा परिषद् में भारत के प्रवेश को सुगम बनाने में साथ दे।

अन्तिम और अभाविप की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बिन्दु, अमेरिका में इस बार के चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बना। भारत के लिये यह और अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी भी परिस्थिति और किसी भी तर्क के आधार पर शिक्षा को बाज़ार के हवाले करने की कोशिशों पर वैसा ही प्रहार ज़रूरी है, जैसा कि काले धन पर किया गया है।

आगामी 24 से 27 दिसंबर को परिषद् का राष्ट्रीय अधिवेशन है जिसमें देशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगे। इस अवसर पर शिक्षा का मुद्दा इस नये सन्दर्भ के साथ सामने आये, यह स्वाभाविक ही है। पूर्वोत्तर, झारखण्ड और केरल-जैसे स्थानों पर परिषद् के कार्यकर्ताओं को छात्रसंघ चुनाव में मिली विजय संगठन की जिम्मेदारी को बढ़ाती है। हम इस कसौटी पर खरे उतरेंगे, यह विश्वास है।

आपका
संपादक

आवरण-कथा

सर्जिकल स्ट्राइक : साहस

भारतीय सेना ने वह कर दिखाया है, जिसकी प्रतीक्षा देश काफी लंबे समय से कर रहा था, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति आड़े आ रही थी। सेना के विशेष दस्ते ने 28 सितम्बर की आधी रात को गुलाम कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक (सीमित सैन्य कार्रवाई) करके वहाँ छिपे आतंकियों को मार गिराया।

■ अजीत कुमार सिंह

उरी हमले के बाद से भारत का गुस्सा चरम पर था। यहाँ की जनता, सरकार को कोस रही थी कि आख़िर कब तक हम अपने जवानों को इस तरह खोते रहेंगे और सिर्फ कड़ी निंदा करते रहेंगे? हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने एक संबोधन में संकेत दे दिया था कि उरी-हमले में शहीद हुए जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। आख़िरकार वह दिन भी आ गया जिसका लोगों को लंबे समय से इंतजार था जब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन (डीजीएमओ) लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के साथ अपनी संयुक्त पत्रकार-वार्ता में कहा कि हमें बहुत ही विशिष्ट और विश्वसनीय जानकारी मिली है कि कुछ आतंकी जम्मू-काश्मीर और अन्य बड़े शहरों में घुसपैठ करने और आतंकी हमले करने की मंशा लिए नियंत्रण-रेखा के उस पार लांचिग पैड पर तैयार बैठे हैं। इसके आधार पर भारतीय सेना ने उन लांचिग पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक किया। इस हमले के दौरान आतंकवादियों और उनका बचाव करनेवालों को भारी नुकसान पहुँचा। बस फिर क्या था, देशभर में सेना की कार्रवाई का गुणगान होने लगा और सरकार व सेना की योजनाबद्ध की गई तैयारी की मुक्तकंठ से प्रशंसा की जाने लगी।

भारतीय सेना ने वह कर दिखाया है, जिसकी प्रतीक्षा देश काफी लंबे समय से कर रहा था, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति आड़े आ रही थी। सेना के विशेष दस्ते ने 28 सितम्बर की आधी रात को गुलाम काश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक (सीमित सैन्य कार्रवाई) करके वहाँ छिपे आतंकियों को मार गिराया। कमांडो दस्ते ने गुलाम काश्मीर में तीन किलोमीटर तक घुसकर आतंकियों के सात लांच पैड तबाह कर दिये। ये लांच पैड बेहद

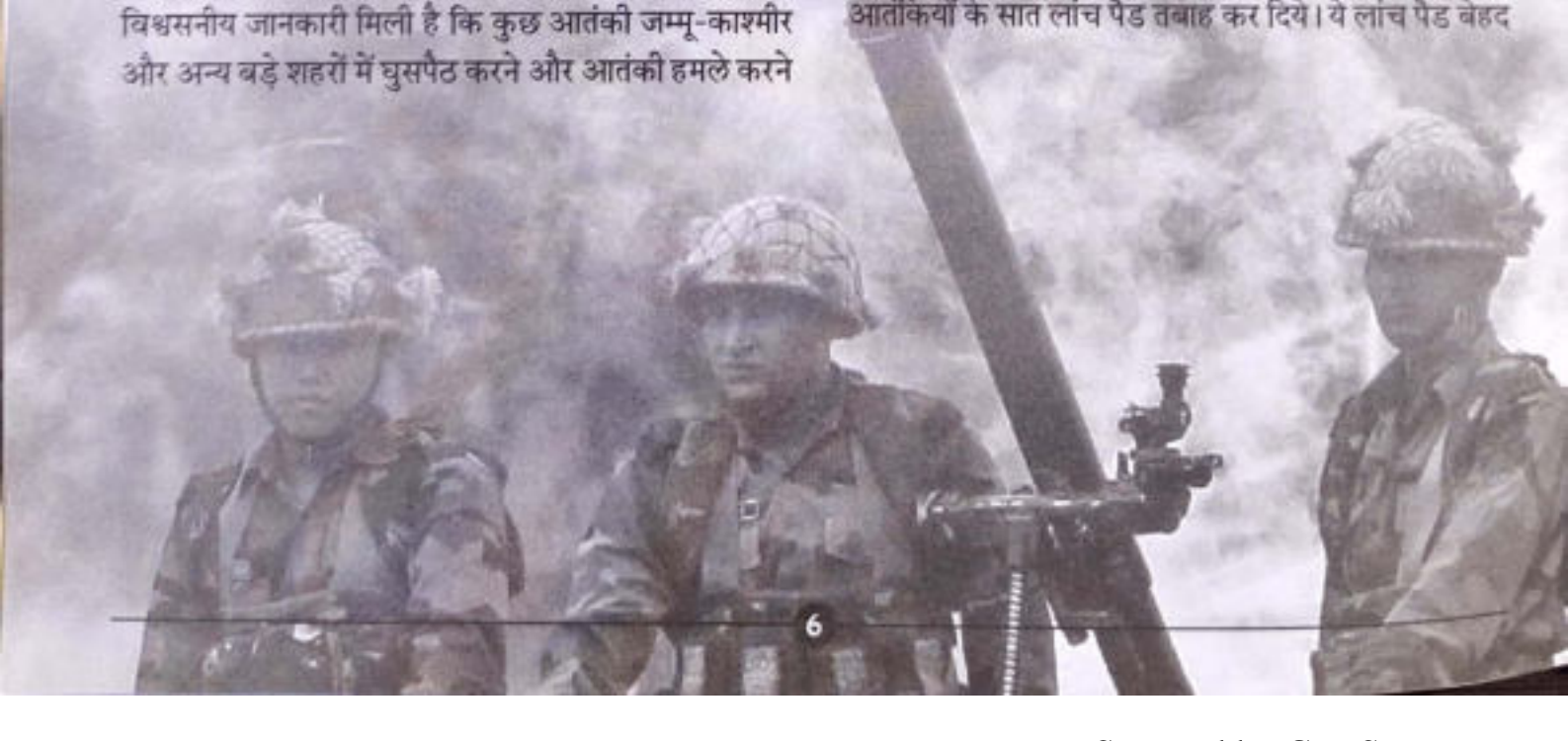

और संकल्प की मिसाल

दुर्गम इलाके में थे। इस ऑपरेशन में 38 आतंकी और दो पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हालांकि चर्चा तो लगभग सौ आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की जा रही है, लेकिन इसकी सरकार या सेना के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। इस सर्जिकल स्ट्राइक में तकरीबन सौ कमांडो ने हिस्सा लिया। सेना के पाँच दस्तों ने भिबंर, केल, तातापानी और लीपा के आतंकी शिविरों को निशाना बनाया।

सीमापार छापामार-शैली में भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई उसके शौर्य और पराक्रम का परिचायक होने के साथ-साथ इसका भी उद्घोष है कि भारतीय नेतृत्व और भारत की जनता पाकिस्तान प्रेरित छद्म युद्ध को और अधिक सहने के लिए बिलकुल तैयार नहीं और यदि उसने अपने तौर-तरीके नहीं बदले तो उसे दंड का भी भागीदार बनना होगा। उरी में पाकिस्तान की धरती पर पनप रहे आतंकियों के हमले ने यह साफ कर दिया था कि अब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा और उसके प्रभावी प्रतिकार का समय आ गया है। महत्त्वपूर्ण यह नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकियों और उसके ठिकानों को कितनी क्षति हुई, महत्त्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान सांबा, कठुआ, गुरदासपुर, पठानकोट और उरी दोहराने के पहले सौ बार सोचने को विवश होगा। पाकिस्तान को इस स्थिति में लाना आवश्यक नहीं अनिवार्य हो गया था। उसे संदेश तो बहुत दिए गए, लेकिन यह सबक सिखाने में देर भी हुई कि वह भारतीय स्वाभिमान को छलनी करते नहीं रह सकता। चूंकि भारत के सहने की सीमा खत्म हो गई थी। इसलिए इस पर आश्चर्य नहीं कि भारतीय सेना की कार्रवाई को सारा देश समर्थन दे रहा है। जब भी कभी सैन्य कार्रवाई की बात होगी तब सेना के साहस और संकल्प की मिसाल के तौर पर इस सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा ज़रूर होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना का मान बढ़ा

भारत के द्वारा आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने की चर्चा आज विश्व-बिरादरी में हो रही है। जर्मनी, अमेरिका सहित विश्व के देश भारत के द्वारा की गई इस कार्रवाई को उचित ठहरा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सेना का मान बढ़ा है। इस कार्रवाई के बाद भारतीय सेना का मनोबल भी काफी बढ़ा है। इससे पहले इस तरह की कार्रवाई की चर्चा सिर्फ इजरायली सेना के सन्दर्भ में होती थी।

सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट

भारत के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की गति सांप-छछंदर वाली हो गई है, न उगलते बन रहा है और न ही निगलते। पाकिस्तान अपने धरती पर किसी भी तरह की

सर्जिकल स्ट्राइक होने से साफ़ इनकार कर रहा है। वह इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि यदि वह इसे स्वीकार करता है तो विश्व-बिरादरी में स्वतः उसके चेहरे बेनकाब हो जाएँगे। लेकिन पाकिस्तान में हो रही हलचल यह साफ़ दर्शाती है कि वह इस कार्रवाई से सदमें में है और काफी बौखला गया है, तभी तो सीमापार से लगातार फायरिंग हो रही है। एलओसी पार कर आतंकी कैंपों को ध्वस्त करने के लिए भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसका नतीजा सीमापार से लगातार सीजफायर तोड़ने की कोशिशों के रूप मे सामने आ रहा है। सीमापार से लगातार गोलीबारी के कारण अभी-तक कई जवान शहीद हो चुके हैं। हालांकि भारत की तरफ से भी मुँहतोड़ जवाब दिया जा रहा है जिससे पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान अब जवानों के साथ-साथ आम लोगों के घरों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के द्वारा लगातार गोलीबारी में कई नागरिक भी मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएँ भी शामिल हैं।

पाकिस्तान सीमापार से बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने के साथ साइबर हमले भी तेज कर रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद गंभीर साइबर हमलों के जरिए भारतीय संवेदनशील सूचनाओं को चुराने का प्रयास किया गया है। इसके जरिए वे लक्ष्य तय करके साइबर हमले कर रहे हैं।

पाक का नापाक चेहरा हुआ बेनकाब...

पाकिस्तान को एक बार फिर अपने कृत्य के कारण शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबो से बाज नहीं आ रहा है। अभी ताजा उदाहरण पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात अधिकारियों द्वारा भारत में जासूसी करने का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात महमूद अख्तर आएसआई से संबद्ध है। उसने दिल्ली के चाँदनी चौक स्थित पते पर महमूद राजपूत के नाम से आधार कार्ड भी बनवा रखा है। इसके साथ और भी कई अधिकारी शामिल हैं। जासूसी करते पकड़ा गया पाकिस्तानी उच्चायोग का अधिकारी महमूद अख्तर पश्चिमी तट पर भारतीय सुरक्षा बलों की तैनाती से जुड़ी गोपनीय सूचनाओं को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। इन सूचनाओं का इस्तेमाल संभवतः 2008 के मुंबई-हमले की तरह ही आतंकी हमले को अंजाम देने में किया जाता। भारत ने महमूद अख्तर सहित अन्य अधिकारियों को पाकिस्तानी उच्चायोग छोड़ने को कहा।

पाकिस्तान ने ज़वाबी कार्रवाई करते हुए अपने यहाँ भारतीय उच्चायोग में तैनात आठ अधिकारियों पर जासूसी का बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उनके नाम और पहचान जारी कर दिया। भारत ने कहा है कि जिस तरीके से आठ भारतीय अधिकारियों के नाम और फोटो प्रकाशित किए गए, सरकार इसका कड़ा विरोध करती है। यह राजनयिक चलन के खिलाफ है। इन अधिकारियों में चार डिप्ल

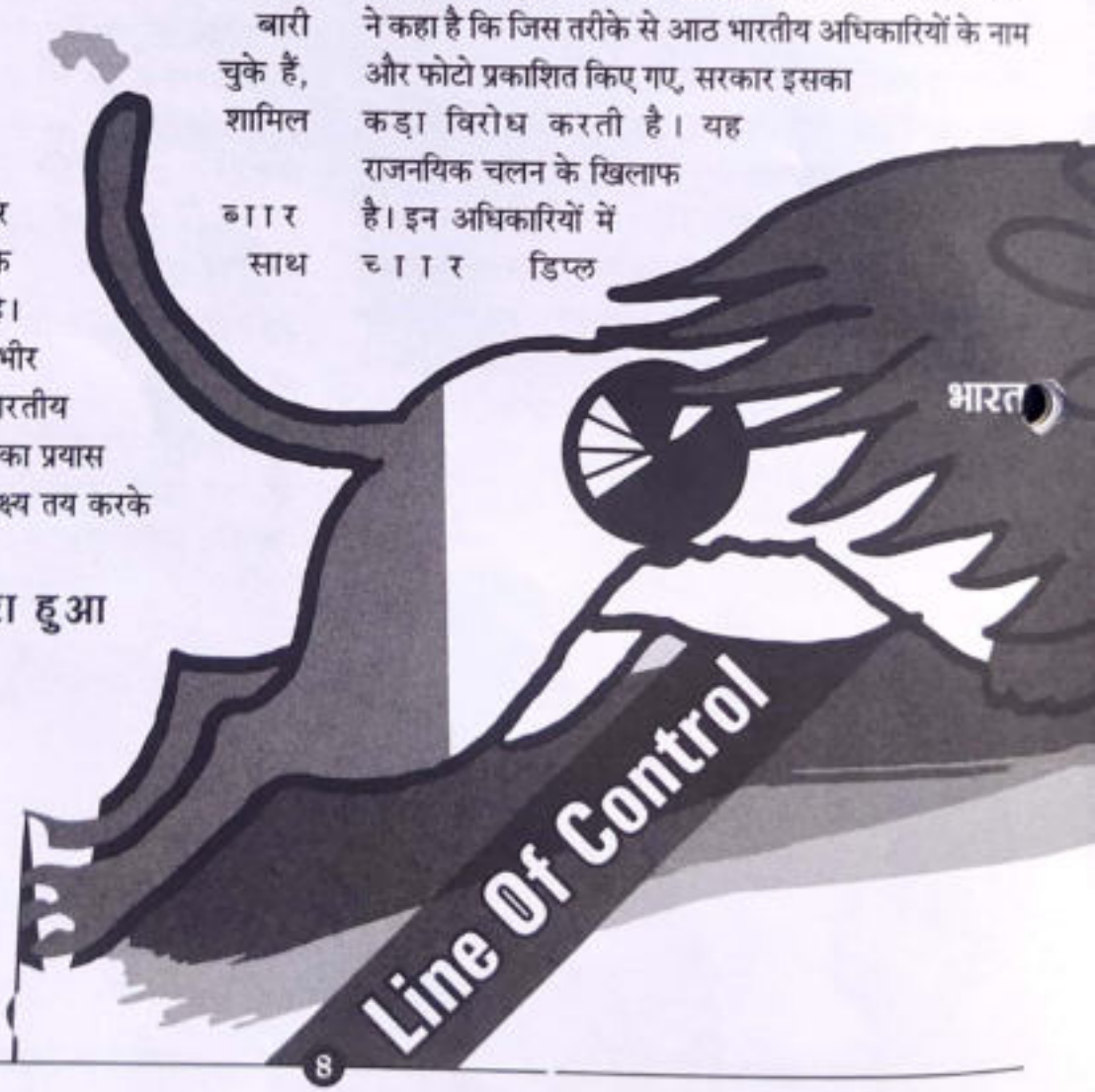

ोमैटिक पासपोर्ट-होल्डर हैं। अधिकारियों के खिलाफ आरोप उनकी सुरक्षा के प्रति भी नुकसानदेह है।

विश्व-बिरादरी में अलग-थलग पड़ा पाकिस्तान

उरी हमले के बाद जिस तरह अमेरिका, रूस, जर्मनी आदि कई देश भारत के समर्थन में आ खड़े हुए है, उससे पाकिस्तान बिल्कुल अलग-थलग पड़ गया है। अमेरिका में तो पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजित देश घोषित करने की ऑनलाइन मुहिम चलाई जा चुकी है जिसमें करीब छः लाख से अधिक लोगों ने अपनी सहमति जताई है। भारत ने इस्लामाबाद में होनेवाले सम्मेलन में शामिल होने में असमर्थता जताई। भारत के दृष्टिकोण से सुखद आश्चर्य यह हुआ कि अन्य देशों– बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और भूटान ने भी भारत के इस रुख का समर्थन किया। नेपाल ने यहाँ तक कहा कि मौजूदा माहौल इस सम्मेलन के आयोजन के अनुकूल नहीं है। उससे पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्तर पर भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। एक देश के लिए इससे अधिक शर्मनाक और क्या हो सकता है कि उसके पड़ोसी देश उससे संपर्क नहीं रखना चाहे। पाकिस्तान को अपनी रीति-नीति पर नये सिरे से विचार करना होगा क्योंकि भारत की तरह बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने उस पर यह आरोप लगाया है कि वह उनके आतंरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका है।

यहाँ ध्यान देनेवाली बात यह है कि अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का महिमामण्डन करने पर नाखुशी जाहिर की थी। काबुल ने बयान जारी कर न सिर्फ दक्षेस सम्मेलन में शामिल होने से इंकार किया, बल्कि खुलकर कहा कि पाकिस्तान उसके ऊपर आतंकवाद थोप रहा है। बांग्लादेश ने भी अपने आतंरिक मामलों मे एक देश के बढ़ते हस्तक्षेप का जिक्र किया। उरी और उसके पूर्व हुए पठानकोट, गुरदासपुर के हठी रवैये को देखते हुए भारत ने उस पर राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव बनाने में सफलता पाई है।

एक तरफ आतंकवादियों को उनके ठिकाने में ही सबक सिखाना, तो दूसरी तरफ विश्व-जनमत में पाकिस्तान को नंगा करना। इन दोनों का परिणाम यह हुआ कि भारत में सरकार की सराहना हो रही है वहीं विश्वभर में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है। इसकी ख़बरें रोज आ रही हैं। सऊदी अरब, अमेरिकी काँग्रेस, अफ्रीकी देशों और दक्षेस में पाकिस्तान पहली बार अपना मुँह दिखाने लायक नहीं रहा है। विश्व-बिरादरी में भारत-सरकार के निर्णय का खुलकर स्वागत हो रहा है। देश के अंदर जो विगत वर्षों में निराशा का माहौल बना हुआ था, वह मिथक टूटा है। किसी राष्ट्र के जीवन में ऐसे क्षण बार-बार नही आते। यह सच है कि विश्व में भारत की साख बढ़ी है। वह समय आ गया है जब आतंक के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के साथ कं धे-से-कं धा मिलाकर साथ चला जाये और आतंक की जड़ को खत्म किया जाय। पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को संचालित कर रहा है, इसमें किसी को भी संदेह नहीं रहा।

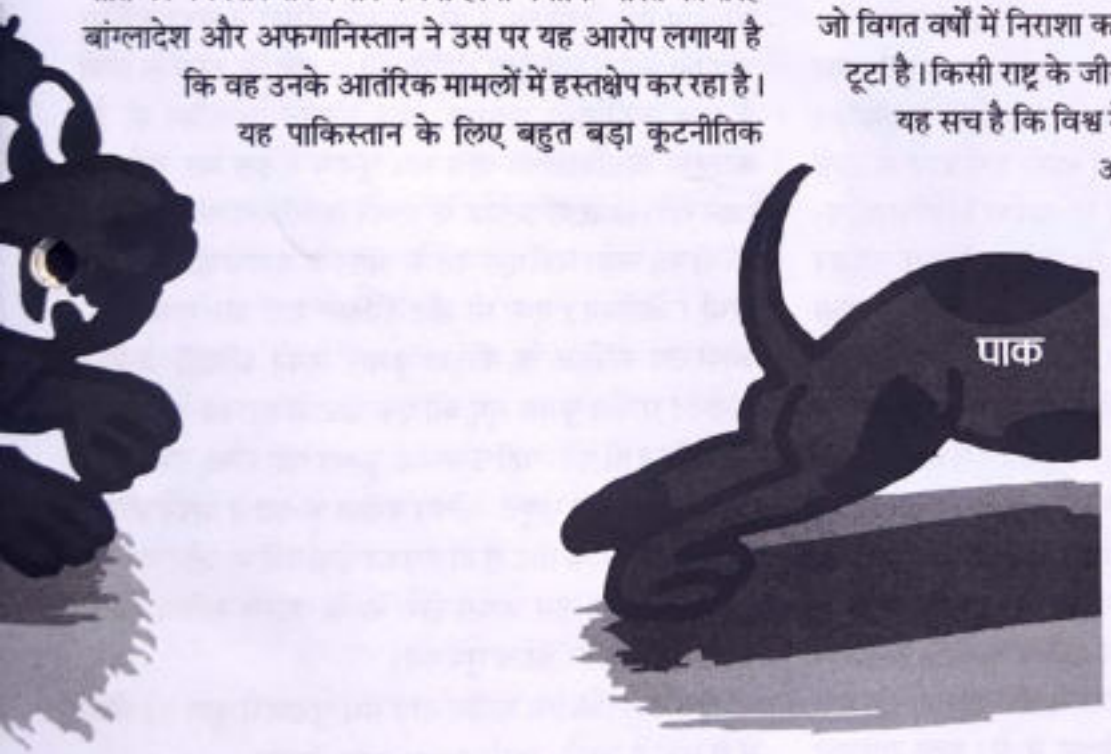

(लेखक राष्ट्रीय छात्रशक्ति पत्रिका में संपादन मंडल सदस्य हैं।)

■

छात्र संघ चुनाव

सारंडा के जंगल में गूँजा वन्दे मातरम्...

झारखण्ड के सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में सभी पदों पर अभाविप की जीत

झारखण्ड के सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय और कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने सभी पदों पर अपना परचम लहराया है। यह जीत कई मायनों में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जहाँ एक तरफ विद्यार्थी परिषद् थी तो दूसरी तरफ बाकी सभी छात्र संगठन एकजुट हो गए थे। जबकि दोनों विश्वविद्यालयों में मतदान की प्रक्रिया भी भिन्न रही। इस बार विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने मतदान कर विश्वविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारियों का चयन किया।

दुमका का सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय झारखंड का वनवासी-बहुल माना जाता है। छात्र संघ चुनाव में इस बार अभाविप और छात्र समन्वय समिति (बाकी सभी छात्र-संगठनों का समूह) के बीच सीधा मुकाबला था। वर्षभर विश्वविद्यालय-परिसर में छात्रहित के लिए सदैव तत्पर रहनेवाली छात्र-संगठन विद्यार्थी परिषद् पर यहाँ के छात्रों ने लगातार तीसरी बार अपना भरोसा जताया है। इससे पहले 2007 और 2008 के छात्र संघ चुनाव में भी विद्यार्थी परिषद् ही जीती थी। विदित हो कि वर्ष 2008 के बाद से ही वि.वि. में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाया था।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रतिनिधियों की संख्या अधिक रहने की वजह से बहुत अधिक अंतर से सभी पदों पर अभाविप के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। सबसे बड़े अंतर से अध्यक्ष पद पर राजेन्द्र मुर्मू और उप सचिव मीनाक्षी कुमारी ने जीत दर्ज की। दोनों ने 20 वोट के अंतर से जीत दर्ज की। राजेन्द्र के विरुद्ध दो उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। छात्र समन्वय समिति के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शिव कुमार हेम्ब्रम को छह वोट पड़े, जबकि वसीम अख़्तर को एक ही वोट मिल पाया। वहीं अभाविप के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित कंचनमाला मुर्मू को 25 मत मिले, जबकि छात्र समन्वय समिति के विकास मुर्मू को 6 मत मिला, सचिव पद पर अभाविप के विश्वराज सिंह को 25 मत मिले वहीं छात्र समन्वय समिति के अमित मंडल को 6 मत मिले, संयुक्त सचिव पद पर अभाविप के सोनू सिंह को 26 मत मिले और उनके प्रतिद्वंद्वी को मात्र 7 वोट मिले। छात्रों ने साबित कर दिया कि सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय रहनेवाले संगठन जीत हासिल नहीं कर सकते।

जबकि नक्सलियों के गढ़ कहे जानेवाले चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी परिषद् ने सभी पदों पर जीत का परचम लहराकर साबित कर दिया है कि छात्रों के दिलों में राज करनेवाला एकमात्र छात्र संगठन अभाविप ही है। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में इस बार काँटे की टक्कर रही। छात्रों के उत्साह के सामने नक्सलियों की धमकी भी फीकी पड़ गयी। वहीं एक मत के अंतर के कारण झारखंड छात्र मोर्चा (जेसीएम) एक भी सीट हासिल नहीं कर सका। को-ऑपरेटिव कॉलेज़ के नीतीश कुमार अपने प्रतिद्वंद्वी जेसीएम समर्थित संजीव कुमार मुर्मू को एक वोट से हराकर अध्यक्ष पद पर काबिज हो गये। वहीं उपाध्यक्ष कृष्णा चंद्रा राणा, उप-सचिव कुणाल सीट तथा संयुक्त सचिव मनीषा कुंदादा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मात्र एक-एक वोट से ही हराकर उक्त पदों पर जीत दर्ज की। जोहार पूर्ति के नाम वापस लेने के के कारण सचिव पद पर शैलेन्द्र गागराई निर्विरोध चुने गये।

कोल्हान वि.वि. स्तरीय छात्र संघ चुनाव में कुल 17 वोटरों में से सभी ने अपने-अपने मत का प्रयोग किया।

यह विश्वविद्यालय नक्सलियों के लिए कुख्यात माने जानेवाले सारंडा जंगल के नजदीक स्थित चाईबासा में है। ऐसे में यहाँ पर अभाविप की जीत काफ़ी महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। ■

केरल में अभाविप ने लहराया जीत का परचम

केरल के तीन विश्वविद्यालय– कालीकट विश्वविद्यालय, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय और कन्नूर विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव के परिणाम यह दर्शाते हैं कि अभाविप पर दिनोंदिन यहाँ के छात्रों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। इस छात्र संघ चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकानेवाला चुनाव परिणाम कन्नूर विश्वविद्यालय का रहा, क्योंकि कन्नूर विश्वविद्यालय हमेशा से वाम छात्र-संगठनों के कब्ज़े में रहा है। कन्नूर विश्वविद्यालय के ग्यारह में से आठ महाविद्यालय के छात्रसंघ चुनाव में अभाविप ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। यह जीत अभाविप के काफी महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है।

कालीकट विश्वविद्यालय के विवेकानन्द महाविद्यालय और एम.वी.एस महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में सारे पदों पर अभाविप-समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है। जबकि 27-28 महाविद्यालयों में दो-तीन पदों पर जीत हासिल हुआ है। शेष जगहों पर विजयी प्रत्याशियों को अभाविप द्वारा कड़ी टक्कर मिली है।

महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम के अंतर्गत आनेवाले इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आई.एच.आर.डी. महाविद्यालय के सभी पदों पर अभाविप ने जीत का परचम

लहराया है। शेष महाविद्यालय के सामान्य पदों पर अभाविप-उम्मीदवारों को एक-दो पदों पर जीत हासिल हुई है। इस छात्रसंघ में काँग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई का सूपड़ा साफ़ हो गया। एनएसयूआई इस छात्रसंघ चुनाव परिणाम में अपने-आपको दूसरे स्थान पर भी नहीं रख पायी।

कन्नूर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव अभाविप के लिए सबसे ख़ास रहा। इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आनेवाले गोविंदापाई मेमोरियल सरकारी महाविद्यालय, मानगेश्वर के सभी आठ पदों पर जीत हासिल कर यह साबित कर दिया है कि वर्षों से अभाविप द्वारा किया गया संघर्ष रंग लाने लगा है। ■

छात्र संघ चुनाव

पूर्वोत्तर में अभाविप की शानदार जीत

अभाविप के द्वारा दो-तीन दशक पहले शुरू की गई एकात्म मानव दर्शन यात्रा, 'पूर्वोत्तर को जानो-देश को जानो' का अथक प्रयास अब रंग लाने लगा। पूर्वोत्तर में हुए छात्र संघ चुनाव में अभाविप की शानदार जीत यह बता रही है कि विद्यार्थी परिषद् किस तरह से वहाँ के छात्रों के दिल में बस चुकी है। अभाविप की विजय-यात्रा पूरे भारत में धूम मचा रही है। दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तराखण्ड और केरल के बाद यह विजय-यात्रा अब पूर्वोत्तर में प्रवेश कर गई है।

हाल ही में सम्पन्न हुए छात्र संघ चुनाव में डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय, गुवाहाटी विश्वविद्यालय सहित पूर्वोत्तर के अन्य कई महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद् ने जीत हासिल की है।

गुवाहाटी विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद् ने पाँच पदों पर शानदार जीत हासिल की। गुवाहाटी के बाद विद्यार्थी परिषद् ने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में दो पदों पर जीत हासिल की है, जिसमें अध्यक्ष पद भी शामिल है।

सिल्चर के राममाधव महाविद्यालय के ग्यारह में से 10 पदों पर अभाविप-प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। शेष एक पद पर किसी भी प्रत्याशी ने चुनाव में भाग ही नहीं लिया था।

रवीन्द्र सदन महाविद्यालय, करीमगंज छात्रसंघ चुनाव के कुल 17 पदों में से 14 पदों पर अभाविप-उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत हासिल की। शेष तीन पदों पर तकनीकी कारणों से चुनाव ही नहीं हो सका।

हैलाकाण्डी-स्थित एस.एस. महाविद्यालय में अभाविप के उम्मीदवार तीन पदों पर विजयी हुए। हैलाकाण्डी के लाला रूरल महाविद्यालय के सभी पदों पर विद्यार्थी परिषद् ने निर्विरोध जीत हासिल की।

ऊपरी असम के उत्तर लखीमपुर ज़िले में स्थित प्रतिष्ठित उत्तर लखीमपुर महाविद्यालय के छात्र एकता चुनाव में अभाविप ने सभी पदों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उत्तर लखीमपुर महाविद्यालय के चुनावों में अभाविप की जीत खासा मायने रखती है, क्योंकि इस कॉलेज़ को उत्तर असम के सबसे बड़ा महाविद्यालय होने का दर्ज़ा प्राप्त है।

असम के अलावा मणिपुर में भी कुछ महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हुए जिसमें अभाविप ने जीत हासिल की है। कुल मिलाकर कहें तो अभाविप पूर्वोत्तर में काफ़ी तेजी से अपनी जड़ें जमा रही है और वहाँ के छात्रों का विश्वास भी जीतने में सफल रही है। ■

वर्तमान शिक्षा-नीति में बदलाव की ज़रूरत : साकेत बहुगुणा

हिसार में आयोजित हुई छात्र महापंचायत

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् विगत 65 वर्षों से विद्यार्थियों की समस्याओं को देशभर में उठाते हुए समाधान के प्रयास कर रही है। विद्यार्थी परिषद् के लिए छात्रहित सर्वोपरि है। हमारे देश के विद्यार्थियों को इतिहास के बारे में वैसी जानकारी नहीं दी जा रही है जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। उन्हें अपने गौरवशाली अतीत का भान तक नहीं है। वर्तमान समय में देश की शिक्षा-नीति में बड़े स्तर पर बदलाव की ज़रूरत है। ये बातें हरियाणा के हिसार-स्थित बरवाला के अंतराम योग आश्रम में आयोजित छात्र-महापंचायत में छात्रों को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय मीडिया-संयोजक साकेत बहुगुणा ने कहीं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में घटी 9 फरवरी की घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि वहाँ के कुछ छात्र देश को तोड़ने व काश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि इन देशविरोधी तत्त्वों के साथ अपने छद्म राजनीतिक हित साधने के लिए राहुल गाँधी, अरविन्द केजरीवाल-जैसे नेता इनसे मिलने जाते हैं। इन नेताओं का देशविरोधी तत्त्वों से मिलना एक विचारणीय प्रश्न है। कुछ लोग जेएनयू परिसर को देशविरोधी गतिविधियों का केन्द्र बनाना चाहते हैं, लेकिन अभाविप ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने देगी। इस अवसर पर श्री बहुगुणा ने वहाँ उपस्थित छात्रों को विद्यार्थी परिषद् से जुड़कर राष्ट्रहित में कार्य करने की अपील भी की।

वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव अंकित सांगवान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बड़ी संख्या में विद्यार्थी राष्ट्रहित में कार्य करते हुए अभाविप के साथ जुड़ रहे हैं। देशभर में विद्यार्थी परिषद् अपना परचम लहरा रही है। छात्र हितों के लिए विद्यार्थी परिषद हमेशा सबसे पहले आवाज़ उठाती रही है। उन्होंने कहा कि जो भी सरकार छात्र हित में कार्य नहीं करेगी, उसका विद्यार्थी परिषद् पुरजोर विरोध करेगी।

महापंचायत को हरियाणा के प्रदेश संगठन मंत्री प्रदीप शेखावत ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की स्थापना की गई थी। अपने स्थापना-काल से लेकर अभी तक परिषद् लगातार व्यक्ति-निर्माण से राष्ट्र-निर्माण के लिए प्रयासरत है। इसके बाद अभाविप के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील भारद्वाज ने विद्यार्थियों की विभिन्न मांगें महापंचायत में रखीं। इसमें मुख्य रूप से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने, प्रवेश-परीक्षा और परिणाम-प्रणाली में पारदर्शिता और समय-सीमा तय करने, शिक्षण-संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भरने, शिक्षा का भारतीयकरण तथा रोज़गारोन्मुख बनाने, लुवास में बीएलडीए के छात्रों के लिए नये छात्रावास का निर्माण, नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू करने, 11वीं व 12वीं में कृषि व पशुपालन विषय लागू करवाने व शिक्षण संस्थानों में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों को विशेष तौर से उठाया गया। महापंचायत के उपरांत विद्यार्थी परिषद् ने उपायुक्त के माध्यम से शिक्षामंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर प्रदेश मंत्री कुलदीप पुनिया, प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत कौशिक, ज़िला प्रमुख नरेश्वर शास्त्री, जिला सह प्रमुख दीपक कुमार, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओम् विष्णु, कौशल घणघस, लुवास संयोजक तरुण सहगल, एचएयू संयोजक मनमोहन भगेल, जिला सह नगरमंत्री मीनाक्षी, विशाल मित्तल, संजय, अजय सहित भारी संख्या में छात्र मौजूद थे। ■

भोपाल में अभाविप की दो-दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला संपन्न

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् की दो-दिवसीय राष्ट्रीय मीडिया कार्यशाला भारतमाता चौक स्थित अभाविप कार्यालय, भोपाल में आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में देशभर के लगभग सभी प्रांत के 104 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें पाँच छात्रा कार्यकर्ता भी शामिल थीं।

कार्यशाला का उद्घाटन अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे ने किया। यह कार्यशाला कुल पाँच सत्रों में सम्पन्न हुई। प्रथम सत्र मीडिया से संबधित विषयों पर आधारित था। इस सत्र में कार्यकर्ताओं को प्रेस विज्ञप्ति बनाने सहित अन्य तकनीकी बातें समझाई गयीं।

दूसरे सत्र में में भाजपा और अभाविप संबध, नक्सलवाद समस्या, सच्चर कमेटी, राजनीति में युवाओं की भूमिका, मुस्लिम छात्रों का अभाविप के प्रति बढ़ता विश्वास, ड्रेस कोड, अल्पसंख्यक-आरक्षण, आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था-जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गयी। चर्चा के उपरांत कार्यकर्ताओं से उनके मन में उठते सवालों को जाना गया और उनके समाधान भी बताए गये।

यहाँ आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से समय-समय पर इस तरह की मीडिया कार्यशाला आयोजन किया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन 2014 में भोपाल में ही हुआ था। कुछ महीने पहले दिल्ली प्रांत के द्वारा भी प्रांत स्तर पर दिल्ली में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

हर प्रांत में हो मीडिया कार्यशाला का आयोजन : आंबेकर

मीडिया कार्यशाला के समापन-सत्र को संबोधित करते हुए अभाविप के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील आंबेकर ने कहा कि इस तरह की मीडिया कार्यशाला का आयोजन हर प्रांत द्वारा किया जाना चाहिए। मीडिया कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। हमारे कार्यकर्ता रचनात्मक रूप से भी मज़बूत होते हैं। सभी प्रांतों में मीडिया के लिए प्रेस-विज्ञप्ति बनाने, मीडिया तक अपने बात पहुँचाने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि मीडिया में अभाविप के विरुद्ध प्रकाशित होनेवाली तथ्यहीन ख़बरों का विरोध करना चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं को अभाविप का इतिहास तथा उसके द्वारा किए गए संघर्ष से संबंधित साहित्य का अध्ययन करना चाहिए।

आंबेकर ने बताया कि परिषद् द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन– शिक्षा-व्यवस्था में सुधार, देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों में छात्रावास की लड़ाई, साथ-साथ छात्रों को हो रही तमाम असुविधा के विरुद्ध प्रशासन के साथ संघर्ष के कार्यों को सही ढंग से मीडिया के माध्यम से जन-सामान्य तक पहुँचाया जा सके, इस उद्देश्य से मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। ■

वामपंथी कुचक्र में फँसा जेएनयू और नज़ीब

ललित पाण्डेय

विश्वविद्यालय, शिक्षा का एक ऐसा प्रतिष्ठान होता है जहाँ शोध, अनुसन्धान और विचार-मन्थन के लिए स्वतन्त्रता व अनुकूलता का वातावरण होना चाहिए। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च शिक्षा में शोध-कार्य की गुणवत्ता और पिछड़े, गरीब व वंचित परिवारों के छात्र-छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, साथ-ही-साथ छात्र-छात्राओं में मानवता, सहनशीलता, तर्कशीलता व सार्थक चिन्तन का विकास करना भी विश्वविद्यालयों का प्रमुख उद्देश्य है। इन सार्वभौमिक आधारभूत मूल्यों के साथ राष्ट्र के एकीकरण, राष्ट्रपरायणता और देश की विविधता को समरसता से विकसित करने के ही उद्देश्य को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की स्थापना की गई जिससे ज्ञान-विज्ञान का प्रचार-प्रसार सर्वत्र होकर ज्ञानरूपी प्रकाश की किरणें प्रत्येक गाँव, कस्बे, शहरों तक पहुँच सकें। लेकिन हाल के वर्षों में जेएनयू चर्चित रहा तो केवल नकारात्मक घटनाओं को लेकर। देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हाल के दौर में किसी अध्यापक या विद्यार्थी के मौलिक काम पर बात ही नहीं सुनाई दे रही है। वह विश्वविद्यालय, जो अपने शिक्षण, अनुसन्धान व मौलिक चिन्तन के लिए विश्वभर में प्रतिष्ठित था, आज वही कुछ वामपंथी संगठनों के क्रियाकलापों से देशभर में आलोचना का केन्द्र-बिन्दु बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि जेएनयू में शोध-कार्य रुक गए हैं। जेएनयू आज भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की क्रीयता-सूची में अभी भी उच्च स्थान बनाए हुए है।

जेएनयू परिसर में जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की बातें होती है और 'अभिव्यक्ति की आजादी' के नारे बुलन्द किए जाते हैं। लेकिन वहीं पर अन्य विचारों का गला घोंटकर मात्र एक विचारविशेष को सर्वगुण और सर्वोपरि उपाधि से विभूषित कर इस विचारधारा को पल्लवित-पोषित किया जाता रहा है। और यह विचारधारा है वामपंथ की। एक ऐसी धारा जो विचार और व्यवहार में बहुत अन्तर समाहित किए हुए है। विचार आज़ादी के होते हैं लेकिन व्यवहार देश को तोड़ने और टुकड़े करने से होता है। विमर्श दलितों, शोषितों और वंचितों को लेकर होता है किन्तु व्यवहार में वह विमर्श वातानुकूलित कक्षों और सिगरेट, शराब से अधिक आगे नहीं जा पाता। कहने को तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करते हैं। माइक्रोसोफ्ट को आने नहीं देते पर इनकी सिगरेट, शराब, जीन्स सब विदेशी ब्राण्ड की होती है। वामपंथियों द्वारा राष्ट्रवाद पर कक्षाएँ ली जाती हैं लेकिन व्यवहार में राष्ट्ररक्षक सैनिकों का अपमान, उनको बलात्कारी कहना, तिरंगे को पैर से कुचलना व जलाना-जैसे देशविरोधी कार्यक्रम किए जाते हैं। बातें प्रगतिशीलता और नारी-सशक्तिकरण की और व्यवहार नारी शक्ति के प्रतीक माँ दुर्गा को वेश्या व अपशब्द कहे जाते हैं। बात और व्यवहार का फर्क वामपंथ के मूल में ही

समाहित है। हाल ही की 14 अक्टूबर की घटना नजीब अहमद के अचानक से गायब हो जाने के मुद्दे पर नज़र डालें तो देखने को मिलता है कि कैसे ये वामपंथीजन आज़ादी का नारा लगाते हुए प्रशासनिक भवन में 22 घण्टे कुलपति, कुलसचिव, रेक्टर, प्रॉक्टर-जैसे अधिकारियों को बन्धक बना लेते हैं।

आख़िरकार क्या कारण हैं जिनसे हमारा विश्व-प्रतिष्ठित जे.एन.यू. बदनाम और इतना अधिक संवेदनहीन होता जा रहा है। इतिहास के पृष्ठों पर जाएँगे तो इस परिसर की अनेक उपलब्धियाँ रही हैं। लेकिन वर्तमान में इस परिसर में अनेक ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिससे छात्रों को शर्मसार होना पडता है और घर से ताने सुनने पड़ते हैं। एक छात्र के द्वारा छात्रा पर कुल्हाड़ी से प्रहार, विदेशी छात्रा के साथ वामपंथी प्रोफेसर द्वारा बलात्कार, एक वामपंथी प्रोफेसर के घर काम करनेवाली नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुराचार, वामपंथी संगठन आइसा के दिल्ली प्रान्त के पूर्व अध्यक्ष अनमोल रतन के द्वारा एक छात्रा के साथ बलात्कार, एक वामपंथी संगठन एआईएसएफ के सदस्य द्वारा छात्रा का यौन-शोषण, कन्हैया कुमार द्वारा शराब पीकर एक पूर्व छात्रा को आपत्तिजनक टिप्पणी व अश्लील अंग-प्रदर्शन जैसी घिनौनी घटनाओं से यहाँ पढ़नेवाले छात्र-छात्राओं को शर्म से सर नीचे करना पडता है।

इतिहास के पृष्ठों पर जाएँगे तो इस परिसर की अनेक उपलब्धिया रही हैं। लेकिन वर्तमान में इस परिसर में अनेक ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिससे छात्रों को शर्मसार होना पडता है और घर से ताने सुनने पड़ते हैं। छात्राओं को शर्म से सर नीचे करना पड़ता है।

आज फिर से एक बार जब जेएनयू के छात्रावासों में चुनाव का माहौल है तो उस पर किस तरह वामपंथी गिरोह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण से अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होना चाहते हैं। नजीब और अन्य तीन छात्रों के बीच मामला एक छात्रावास की घटना थी जिसमें नज़ीब के द्वारा विक्रान्त पर थप्पड़ मारकर हमले की कोशिश की, मामला छात्रावास वार्डन के समक्ष सुलझ गया, जिसमें जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के हस्ताक्षर हैं लेकिन अगले दिन वामपंथियों की विचार बैठक में निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को लेकर चुनाव में माहौल बनाना चाहिये। आनेवाले दिनों में इस अल्पसंख्यक कार्ड से जेएनयू में यहाँ के वामपंथी प्रोफेसरों ने उस घटना को धर्म से जोड़कर राजनीतिक रोटियाँ सेंकने का कुचक्र बनाना आरम्भ किया। और फिर इस तरह नज़ीब का उस रात को मोहित पाण्डेय (छात्र संघ अध्यक्ष), कासिम (कन्वेनर और काउंसलर, एस एल और सीएस), उमर खालिद और अनिर्बाण के साथ दिखना, उसका गायब होना वामपंथियों को कटघरे में खड़ा करता है।

उन्नीस अक्टूबर की दोपहर में जेएनयू छात्र संघ के आन्दोलनकारियों ने प्रशासनिक ब्लॉक का घेराव किया और भवन को चारों तरफ से घेरकर सभी रास्तों को बन्द कर दिया व अगले 22 घण्टों तक अवैध रूप से कुलपति, रेक्टर, कुलसचिव, प्रॉक्टर व अन्य लोगों को कैद कर लिया। करवा चौथ की उस रात को उनके परिजनों को उनसे नहीं मिलने दिया गया। मधुमेह और अन्य बीमारीवाले अधिकारियों को भी घर नहीं जाने दिया गया।

इस तरह आज़ादी की मांग करनेवाले वामपंथी गिरोह ने खुद अधिकारियों को बन्धक बनाया हुआ था। हालाँकि इस पूरे विवाद में नज़ीब अहमद गौण हो चुका है। चारों ओर भय, आतंक और भ्रम का भयावह वातावरण बनाकर वामपंथी अराजक तत्त्वों के साथ मिलकर देश के सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ते हुए एक बड़ा आन्दोलन करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली 15 तारीख़ से जेएनयू में कक्षाओं को रोका जा रहा है, परीक्षाओं को जबरन रद्द करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

वाम गिरोह की जाति व धर्म की राजनीति को अब साम्प्रदायिक रूप दिया जा रहा है। शिक्षक एसोसिएशन के द्वारा छात्रों को जबरन विरोध-प्रदर्शन के लिए बुलाया जा रहा है। व्यवस्था व क़ानून को अपने हाथ में लेकर समाज-विभाजन व साम्प्रदायिकता का वातावरण निर्माण किया जा रहा है।

आज कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब देने में जेएनयू परिसर के वामपंथी कतरा रहे हैं और मुँह छुपाए इधर-उधर भाग रहे हैं।

1. पहले तीनों वार्डन व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, मोहम्मद कासिम आदि के समक्ष नज़ीब ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर उस पर उक्त सभी लोगों ने नजीब अहमद पर कार्यवाही की जाए– इस प्रकार के पत्र में हस्ताक्षर किये। लेकिन अब वह बयान बदल रहे हैं कि अभाविप ने मारा जबकि उन्होंने पत्र में स्वीकार किया है कि हमला नज़ीब के द्वारा हुआ। यदि इस घटना में अभाविप की तथाकथित भूमिका थी तो 14 अक्टूबर की रात को वार्डन-छात्र मीटिंग में अभाविप के विरोध में एक भी आरोप क्यों नहीं दर्ज़ किए गए?
2. यदि वामपंथियों के अनुसार नज़ीब को चोट आई या मारपीट हुई तो घटना के तुरन्त बाद जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष ने मेडिकल जाँच क्यों नहीं करवाया? क्या नज़ीब की मेडिकल जाँच से मीटिंग अधिक महत्त्वपूर्ण थी? यदि नज़ीब को चोट आई होती तो उसकी मेडिकल जाँच अवश्य की जाती।
3. जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष माही-माण्डवी के छात्रों को औकात में रहने की धमकी व अपशब्दों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्या छात्र संघ के नेता का व्यवहार इस तरह का होना चाहिए?
4. तीनों छात्र– विक्रान्त, अंकित, सुनील से अभी तक कोई छात्र संघ की तरफ से क्यों नहीं मिला? क्या ये छात्र जेएनयू परिवार के नहीं हैं? क्या जेएनयू छात्र संघ मात्र वामपंथियों का है या फिर पूरे जेएनयू का?
5. नजीब के रूममेट मोहम्मद कासिम (कन्वेनर और काउंसलर, एस एल और सीएस) ने 14 अक्टूबर की रात को नज़ीब के खिलाफ एक पत्र लिखकर उसे खतरनाक और बदमाश कहा था, तो फिर आखिर अपने संगठन (एआईएसए) के दबाव में आकर 15 अक्टूबर से नज़ीब कासिम के लिए सीधा और सरल कैसे हो गया?
6. क्या थप्पड़ खाने के बाद शिकायत करना अपराध है? जो कि विक्रान्त ने किया और बाद में नज़ीब ने भी स्वीकारा।
7. क्या जेएनयू की शिक्षा-व्यवस्था को अवरुद्ध कर और प्रशासनिक अधिकारियों को बन्धक बनाकर नज़ीब वापस आ जायेगा?
9. तीनों छात्रों की सुरक्षा व नज़ीब को वापस लाने की ज़िम्मेदारी किसकी है?

आज वामपंथी प्रोफेसर छात्रों का प्रयोग कर विश्वविद्यालयों को शिक्षा से दूर ले जाकर एक विचारधारा को थोपना चाहते हैं। दलित, जनजाति, मुस्लिम, ईसाई, अल्पसंख्यकों के नाम राजनीति करते हुए मोदी, संघ, भाजपा, अभाविप पर निशाना साधा जाता है और भगवाकरण के आरोप लगाए जाते हैं। वामपंथी प्रोफेसर छात्रों से शोधकार्य से अधिक प्रतिशोध कार्य को बढ़ावा देते हैं। वामपंथ की वह राजनीति, जो देशभर से खत्म हो चुकी है, उसे पुनर्जीवित करने के लिए देश के परिसरों को समाज-विभाजन कर राजनैतिक क्यारियाँ बनाकर उनमें विषबेल बढ़ाई जा रही है, और इन क्यारियों में रोहित तथा नज़ीब-जैसे प्रबुद्ध छात्रों को खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज वामपंथियों को सोचना होगा कि कहीं अपनी खोई हुई ज़मीन को खोजते-खोजते वे आतंकवादियों, नक्सलियों और देशविरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन रहे हैं?

(लेखक अभाविप जेएनयू इकाई के सचिव हैं)

प्रिय मित्रो !
शिक्षा-क्षेत्र की प्रतिनिधि-पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' का नवम्बर, 2016 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसमें विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों और ख़बरों का संकलन किया गया है। आशा है, यह अंक आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें :

संपादक, 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
'छात्रशक्ति भवन',
26 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नयी दिल्ली-110002.
फोन : 011-23216298
Visit us at : www.abvp.org

chhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/chhatrashakti
www.twitter.com/chhatrashakti1

नीतीश सरकार का दलित-विरोधी चेहरा उजागर हुआ : विनय बिदरे

जब पूरा देश अत्याचार और शोषण से पीड़ित था, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना की धरती से ही सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। लेकिन आज दुर्भाग्यवश 1974 के छात्र आंदोलन की उपज नीतीश कुमार के शासन में बिहार के दलित-छात्रों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलित वर्गों को दलित-महादलित में बाँटकर सिर्फ़ राजनीति की, लेकिन उनके शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में कुछ नहीं किया। अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती कर प्रदेश सरकार ने अपने दलित-विरोधी चेहरे को उजागर किया। ये बातें अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री विनय बिदरे ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की विभिन्न समस्याओं को लेकर पटना में निकाली गई विशाल छात्र हुंकार रैली में छात्रों को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में अ.जाति/ज.जाति छात्रों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। प्रदेश में छात्रवृत्ति में बड़े पैमाने पर लूट मची है। करोड़ो रुपये जो इन छात्रों को मिलना चाहिए था उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है।

यहाँ बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की समस्याओं, छात्रवृत्ति में लूट, छात्रावास की नारकीय स्थिति आदि को लेकर दलित छात्रों की विशाल रैली, हुंकार मार्च निकाला। पटना के राजेन्द्र नगर स्थित शाखा मैदान से हज़ारों की संख्या में निकलकर पटना

विश्वविद्यालय पहुँचे। पुलिस ने आयोजन के पहले ही सभी छात्रों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और पटना विश्वविद्यालय को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। इस दौरान अभाविप के महानगर मंत्री सहित करीब 11 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई।

इस रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश सह-संगठन मंत्री सुधीर कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश में कल्याण छात्रावास की स्थिति नारकीय बनी हुई है। वर्षों से छात्रावास नहीं बनने के कारण अ.जाति/जनजाति छात्रों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में छात्रावासों में पानी, बिजली-जैसी मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं है।

इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विकास के बड़े-बड़े दावे करनेवाले वर्तमान सरकार के दावे अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की परिस्थिति देखने के बाद खोखले साबित हो रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति की साक्षरता-दर मात्र 28.5 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 54.69 प्रतिशत है। वहीं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता-दर मात्र 28.2 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 47.10 प्रतिशत है। छात्रों के पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति-योजना में बड़े पैमाने पर फर्जी इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं फर्जी छात्रों के नाम पर लूट मची हुई है। पोस्ट-मैट्रिक (तकनीकी संस्थान) में अध्ययनरत दलित छात्रों को मिलनेवाली छात्रवृत्ति की राशि में बिहार सरकार ने कटौती कर दलित समुदाय के साथ बदसलूकी की है। नीतीश कुमार ने नामांकन मेला लगाकर

अ.जाति/जनजाति छात्रों को इंजीनियरिंग कॉलेज़ में नामांकन लेने को कहा। अब तीसरे साल में सरकार 15,000 रुपये छात्रवृत्ति देने की बात कह रही है। 2014-15 के सत्र में नामांकन लेनेवाले छात्रों ने किसी को एक साल की तो किसी को दो साल की ही छात्रवृत्ति मिली है। शुल्क नहीं देने के कारण छात्रों को महाविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया है। दलित छात्रों के लिए बिहार सरकार कितनी संजीदा है, इसका पता इसी से चलता है कि वर्ष 2015-16 में 1 लाख 11 हज़ार छात्रों के आवेदन आए जिसमें मात्र 20,000 को ही छात्रवृत्ति दी गई। सभा को संबोधित करनेवालों में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमुख गौरव रंजन, प्रदेश सह-मंत्री सुजीत पासवान आदि थे। सभा के उपरांत मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपाधीक्षक के माध्यम से 21 सूत्री मांग-पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंपा।

बाद में इन मांगों को लेकर अभाविप का 11-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल बिहार के महामहिम राज्यपाल से मिलकर अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों की समस्याओं का मांग-पत्र सौंपा। महामहिम ने जल्द समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर अभाविप के क्षेत्रीय संगठन मंत्री गोपाल शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री निखिल रंजन, प्रदेश मंत्री दीपक कुमार, सहित हज़ारों की संख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र मौजूद थे। ■

संघ लोकसेवा आयोग के खिलाफ अभाविप का प्रदर्शन

सिविल सेवा परीक्षा में हिंदीभाषी तथा भारतीय भाषी छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप

इलाहाबाद। संघ लोकसेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा-पद्धति में विभिन्न परिवर्तन के कारण विद्यार्थियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। हिंदी-पट्टी के छात्रों के प्रतिनिधित्व का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है जिस कारण हिंदी एवं भारतीय भाषी छात्रों में काफी रोष है। छात्रों का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर आ गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के बैनर तले छात्रों एवं प्रतियोगियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक संघ लोकसेवा आयोग के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। अभाविप सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आयोग की परीक्षाओं में निरंतर हुए परिवर्तनों का विरोध किया।

छात्रों का कहना है कि सिविल सेवा में वर्ष 2011 से 2014 तक निरंतर परिवर्तन किए गए हैं। इन परिवर्तनो के फलस्वरूप हिंदी एवं भारतीय भाषी तथा गैर-तकनीकी माध्यम के छात्रों को इस दोषपूर्ण तकनीक के माध्यम से बहुत अवसर गँवाने पड़े हैं। 2011 में सीसैट लागू किया गया। इसपर अध्ययन के लिए बनी 'निगवेकर कमेटी' ने इसे दोषपूर्ण पाया था। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट से भी साफ जाहिर होता है कि जहाँ 2010 तक हिंदी तथा भारतीय भाषी तथा गैर-तकनीकी विषय के छात्रों के मुख्य परीक्षा में प्रतिनिधित्व 48.5 फीसदी तक होता था वहीं 2015 तक आते-आते यह 11 फीसदी रह गया है।

उनलोगों का कहना है कि सिविल सेवा भर्ती परीक्षा प्रारूप की समीक्षा के लिए पूर्व में गठित 'बासवान समिति' ने आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा 27 साल किए जाने की सिफारिश की है। इससे हिंदीभाषी तथा ग्रामीण परिवेश के प्रतियोगियों के लिए अवसर और घट जाएँगे। छात्र इस सिफारिश को नकारने की मांग कर रहे थे। दोषपूर्ण परीक्षा-प्रणाली से प्रभावित छात्रों को अतिरिक्त अवसर दिया जाय। हिंदी एवं भारतीय भाषी छात्रों के अन्तिम चयन में लगातार घटते प्रतिनिधित्व की जांच कर भेदभाव खत्म किया जाए। ज्ञापन सौंपनेवालों में रोहित मिश्र, रजनीश, रिंकू, देवेन्द्र, विक्रम सिंह, बृजेश आदि कई छात्र उपस्थित थे।

रानी लक्ष्मीबाई

महिला सशक्तीकरण की प्रेरणा

नयना सहस्त्रबुद्धे

आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सुनहरा पन्ना है। रानी लक्ष्मीबाई का जीवनकाल बहुत ही छोटा (1835 से 1858) रहा, लेकिन उनका कार्य और जीवन स्त्री की शक्ति, क्षमता और कठिन समय में नेतृत्व देने की क्षमता का उदाहरण है। 19 नवंबर, 1835 को जन्म, 14 वर्ष की आयु में झाँसी के राजा गंगाधरराव नेवालकर के साथ ब्याह, 1851 में पुत्र का जन्म, सब तत्कालीन सामाजिक-परिवारिक स्थिति-गति अनुसार ही था।

परंतु विशेषता यह थी कि लक्ष्मीबाई झाँसी की रानी थी। चार महीनों की अति अल्पायु में बेटे की मृत्यु हो गयी। ब्रिटिशों का राज था, ब्रिटिश सरकार भारत के राजे-रजवाड़े की सम्पत्ति और सत्ता को खारिज़ करने पर तुला था। पति-पत्नी ने सोच-विचारकर दामोदरराव को गोद लिया। पुत्र-वियोग के दुःख से ही राजा गंगाधरराव का निधन हो गया। यह इतिहास तो हम सब जानते हैं, विशेषता यह थी मोरोपंत तांबे की पुत्री होने के कारण मणिकर्णिका-लक्ष्मीबाई को शिक्षा की तालीम मिली थी। राजनीति का ज्ञान मिला था। 'रानी' होने के नाते सल्तनत की जिम्मेवारी निभाने का जुनून उनमें था। सशक्तीकरण की बात व्यक्ति के अंदर से निकलनी चाहिये और बाहरी वायुमण्डल का अगर आधार मिले तो ही सशक्त व्यक्तित्व का दर्शन होता है। रानी लक्ष्मीबाई इसकी मिसाल हैं।

अंग्रेज़ों का रुख़ देख-समझकर राज्य को वारिस देने के लिए बच्चा गोद लेने का निर्णय हो, अंग्रेज़ों के साथ पत्राचार हो, लंदन में अपील करना, प्रजा को राज्य के रक्षण के लिए प्रोत्साहित करना, खुद मार्शल आर्ट सीखना और महिलाओं का सशस्त्र दल तैयार करना, लड़ाई का नेतृत्व तैयार करना, यह उनके अद्भुत और सशक्त व्यक्तित्व का परिचय है।

ऐसे गरिमामय उदाहरण सामने होते हुए, शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, क़ानूनी सहयोग, प्रोत्साहन का वातावरण और वायुमण्डल सामाजिक-पारिवारिक-राजनैतिक स्तर पर भरपूर अवसर होते हुए भी आज की तारीख में महिला सशक्तीकरण का विचार करने की आवश्यकता लगती है। मेरी दृष्टि से इसका कारण अंदरूनी चेतना का अभाव है। महिला सशक्तीकरण की कोई एक व्याख्या नहीं है। उसके कई पहलू हैं। स्वायत्तता, स्वनिश्चय, निर्णय-प्रक्रिया में सहभागिता, जिम्मेवारी का निर्वहन, लक्ष्य हासिल करना ऐसे गुणों का समूह जहाँ हो, वहाँ आपको सशक्तिकरण का एहसास होगा। अभाव को प्रभाव तक लेकर जाना– यह सशक्तिकरण की ओर लेकर जानेवाला प्रवास है। 'सशक्तीकरण'– इस शब्द में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, राजनैतिक सशक्तिकरण की बात तो है ही, परंतु लिंग-आधारित समानता– यह महिला-सशक्तीकरण का महत्त्वपूर्ण पहलू है।

स्त्री और पुरुषों में शरीर-रचना, स्वभाव, प्राकृतिक दायित्व– ऐसे अनेक मुद्दों पर भिन्नता है। किन्तु जब यह 'भेद' समाज और संस्कृति द्वारा भेदभाव में परिवर्तित होता है, तो यह बात चिंता की भी है, चिंतना की भी है। प्राचीन भारत में महिला का स्थान, मान-सम्मान, पुरुष के समान था, इसके कई उदाहरण

मिलते हैं। परकीय आक्रमण तथा समाज की अवनत स्थिति के कारण वह और अवनत हो गया। यह भी हम जानते हैं लेकिन गत दो सौ वर्षों में हम नारी की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में सफल हो रहे हैं। अभी भी बहुत बड़ा फासला हमें काटना है, फिर भी विश्व के अन्य समाज-समूहों के नारी-जगत् के बारे में जो चिंतन सामने आता है, वह देखकर लगता है भारतीय नारी को ही महिला सशक्तिकरण के विषय में संसार का नेतृत्व करने की आवश्यकता है।

विज्ञान ने स्त्री-पुरुष को समान पाया है। विज्ञान का क्षेत्र तर्क-प्रमाण-तथ्य का क्षेत्र माना जाता है, होना चाहिये, परंतु आज भी कई मानव समूह नारी को शत-प्रतिशत मानवी नहीं मानते हैं। इसके कई सबूत व्यवहार में मिलते हैं। इसलिये आज भी महिला-सशक्तीकरण के बारे में सोचना पड़ता है।

मुश्किल है, परंतु महिला-सशक्तीकरण को मापने के कुछ मापदण्ड हम मान सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, कुरीतियों से बचाव, मताधिकार, नौकरी के अवसर, राजनीतिक-सामाजिक नेतृत्व के अवसर, कार्यस्थल पर आते हैं जिसमें गत 70 वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। स्वाधीनता आन्दोलन से लेकर अनेक सामाजिक विषयों में न केवल महिलाओं की सहभागिता रही है, अपितु वह नेतृत्व भी कर रही है। बैंक से लेकर कई आर्थिक आस्थापनों का नेतृत्व कर रही है। विज्ञान के तंत्रज्ञान के क्षेत्र में भी वह आगे हैं, मंगलयान मुहिम से लेकर लड़ाकू विमानों तक हर जगह वह आगे है। लेकिन गिनी-चुनी महिलाएँ इस उड़ान को हासिल करती है, आज भी राजनीति से अनुसंधान तक महिलाओं का प्रतिशत 20 से 25 प्रतिशत ही रहा है। समानता की ओर हमें ऊँची उड़ान, लंबी छलांग अभी भी लगानी है।

व्यवस्था आज स्त्री अनुकूल हो रही है, सतर्कता से इस व्यवस्था-निर्माण में सहभागी होना आवश्यक, अनिवार्य है ही, उससे महत्त्वपूर्ण है नारी का खुद में बुलंदी लाना, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, स्वयं को जानना। Sence of the self worth, self esteem, respect & dignity वह महिला सशक्तीकरण का आविष्करण है, ऐसा मेरा मानना है।

महिला-सशक्तीकरण इतना महत्त्वपूर्ण क्यों है? सशक्त नारी यानि सशक्त परिवार यानि सशक्त देश यह हम जानते हैं। परंतु विश्व का आधा हिस्सा महिलाएँ, उनकी प्रतिभा और क्षमता बरसों से परिवार की चहारदीवारों तक सीमित थी। चीन की आर्थिक प्रगति का कारण महिलाओं का वर्कफोर्स में आना माना जाता है। भारतीय पारंपारिक उद्योगों में और खेती में महिला की हमेशा सहभागिता रही है, लेकिन इस घरेलू श्रम को आर्थिक दृष्टि से कभी नापा नहीं गया है। जिसकी आवश्यकता भारत में गत 20 वर्षों से चली स्व-सहायता गुटों की मुहिम भी गाँव-कस्बे में रहनेवाली महिलाओं की आर्थिक सशक्तीकरण का कारण बनी है। पंचायती राज में 50 प्रतिशत मिला आरक्षण कम पढ़ी-लिखी महिलाओं ने अपनी सोच-विचार-विवेक की ताकत के आधार पर सफल बनाया है।

रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण बुलंद हौसले, स्व-क्षमता के बारे में निःसंदेह विश्वास, नेतृत्व और कर्तव्य का उदाहरण है। उनका स्मरण करते हुए चेतना का जागरण और पूरक व्यवस्था निर्माण के आधार पर महिला सशक्तीकरण यानि परिवार और समाज का सशक्तीकरण– यह हमारा ध्येय होगा।

इनके कारण पारिवारिक हिंसा कम होती दिखाई देती है लेकिन सामाजिक हिंसा, असुरक्षा, यौन-हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण ऐसे मुद्दों से वह पीड़ित है, चिंतित है। आज की नारी उड़ान भरने की क्षमता रखती है, परंतु पुरुष मानसिकता में परिवर्तन लाने की ज़बरदस्त चुनौती अपने-सामने है। स्त्री-पुरुषों में भेद है, उसका स्वीकार, भेदभाव को समाप्त करना, नारी के अधिकार-मान-सम्मान का परिवार में पुनर्स्थापित करना, उसकी क्षमता और प्रतिभा को परिवार-समाज और राष्ट्र के निर्माण में उपयोग करना, स्त्री-पुरुष तुलना के बजाय स्पर्धापूरक बनना और समान गति, सहारे एक दूसरे के विकास के लक्ष्य को हासिल करना यह महिला-सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ है।

रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण बुलंद हौसले, स्व-क्षमता के बारे में निःसंदेह विश्वास, नेतृत्व और कर्तव्य का उदाहरण है। उनका स्मरण करते हुए चेतना का जागरण और पूरक व्यवस्था निर्माण के आधार पर महिला सशक्तीकरण यानि परिवार और समाज का सशक्तीकरण– यह हमारा ध्येय होगा। छात्र शक्ति इस चुनौती का स्वीकार करेगी, यह मेरा विश्वास है।

(लेखिका भारतीय स्त्री शक्ति की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं)

राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की भूमिका अहम : जी. लक्ष्मण

आज हमारे देश की जनसंख्या में से 35 से 40 प्रतिशत की आबादी युवावर्ग की है। वर्तमान समय में विश्व का सबसे युवा देश भारत है। युवावर्ग जो चाहे कर सकता है। युवावर्ग समाज को जिस राह में ले जाना चाहेंगे, हमारा देश उसी दिशा में जायेगा। देश का भविष्य युवाओं के कंधे पर है, अब इन्हें ही तय करना है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। इस देश में भारत के विरोध में नारे लगानेवाले लोग हैं तो 'भारतमाता की जय' का नारा लगानेवाले और देश के लिए बलिदान देनेवाले युवा भी हैं। एक समय हमारा देश विश्वगुरु था। दुनिया के लोग यहाँ शिक्षा लेने आते थे। हमारा देश शक्तिशाली था, शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद हमारे देश ने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया और न किसी पर अत्याचार किया। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति में कहा गया है कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और विश्व-कल्याण की भावना ही हमारी विरासत है। युवाओं के अथक प्रयास का ही परिणाम है कि आज भारत तेजी से आगे बढ़नेवाले देशों की श्रेणी में है। इस देश के युवा समाज के हर वर्ग में अपना परचम लहरा रहा है। राष्ट्र-निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। ये बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के राष्ट्रीय सह-संगठन मंत्री जी. लक्ष्मण ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती सांध्य कॉलेज में अभाविप द्वारा आयोजित **'राष्ट्रनिर्माण में युवाओं की भूमिका'** विषय पर छात्रों को संबोधित करते हुए कहीं।

उन्होंने युवाओं के बारे में बताते हुए कहा कि विश्व की 25 बड़ी-बड़ी कंपनियों के सी.ई.ओ. भारतीय हैं। हमारे देश के युवा देश में ही नहीं विदेशों में भी अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। पहले की अपेक्षा वर्तमान में विश्व के मानस पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा है। जब देश के सम्मान की बात आती है, ये युवा बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जिस कारण आज राष्ट्र इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करके हर क्षेत्र में ज्ञान हासिल करना चाहिए ताकि आप विश्व का नेतृत्व कर सकें। यदि हमें आगे बढ़ना है तो नकारात्मक सोच को त्यागकर सकारात्मक बातों पर ध्यान देना होगा।

कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश के प्रांत प्रमुख राजकुमार शर्मा, प्रदेश मंत्री भरत खटाना, इकाई-अध्यक्ष, विभाग संयोजक पंकज, ज़िला-संयोजक सचिन बैसला सहित सहित सैकड़ों छात्र मौजूद थे। ■

इंदौर में होगा अभाविप का 62वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का 62वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर (मध्यप्रदेश) में 24 से 27 दिसम्बर को आयोजित होना है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगगुरु स्वामी रामदेव उपस्थित होंगे। अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा के साथ शिक्षा और देश से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव पारित होंगे। इसके अलावा उद्घाटन समारोह, प्रास्ताविक, महामंत्री प्रतिवेदन, भाषण, युवा पुरस्कार प्रदान समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं समापन समारोह आदि कार्यक्रम का आयोजन होगा।

राष्ट्रीय अधिवेशन 24 दिसम्बर, 2016 को ध्वजारोहण से प्रारम्भ होकर 27 दिसम्बर, 2016 को नयी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा के साथ सम्पन्न होगा। इस दौरान अलग-अलग विषयों पर सत्र चलेंगे तथा विभिन्न मुद्दों पर कई प्रस्ताव को भी पारित किया जायेगा। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय महामंत्री का चुनाव भी किया जायेगा। अधिवेशन में प्रो. यशवंतराव केळकर युवा पुरस्कार भी प्रदान किया जायेगा।

अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के अलावा, सभी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, सभी जिला-विभाग एवं विश्वविद्यालय-संयोजक, सभी नगर मंत्री, विश्वविद्यालय परिसर इकाई के अध्यक्ष व मंत्री देशभर के पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विश्वविद्यालय के छात्र संघ पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही, विकासार्थ विद्यार्थी, थिंक इण्डिया, सहित अभाविप के विभिन्न आयामों के कुछ कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्राएँ सम्मिलित होंगी। इस बार अधिवेशन में देशभर के लगभग 8,000 से भी अधिक कार्यकर्ताओं के आने की संभावना बताई जा रही है।

मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें ए.एम.यू. उपाध्यक्ष : डॉ. प्रभाकर रॉय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के माही-माण्डवी छात्रावास से लापता छात्र नज़ीब जंग की रिहाई को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ ने एक मार्च निकाला जिसमें एएमयू के छात्र के उपाध्यक्ष के द्वारा अभाविप-नेताओं के विषय में अपशब्द कहे गये जिससे अभाविप-कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।

अभाविप के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रभाकर रॉय ने कहा है कि एएमयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। अभाविप इस प्रकार के ग़ैर ज़िम्मेदाराना बयान की कड़ी निन्दा करती है।

उन्होंने कहा कि अभाविप के ऊपर इस तरह की बयानबाज़ी करना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है या फिर कह सकते हैं कि यह बयान उनकी बौखलाहट का परिचायक है। चूंकि अभाविप देशहित के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर उठाती रही है, इस प्रकार के अनर्गल बयान जो दे रहे हैं, उससे पहले वे एएमयू में दलितों और पिछड़ों को संविधान के तहत जो हक़ मिलना चाहिए उसकी आवाज़ यदि बुलंद करते, तो शायद अच्छा संदेश जाता। जो देशद्रोही गतिविधि करते हैं, एएमयू में दलित पिछड़ों का हक़ देना नहीं चाहते, उनके बारे में बात करते तो साहस दिखता। एएमयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष इस तरह की फालतू बयानबाजी करके एएमयू व शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। विद्यार्थी परिषद् कभी भी धर्म व जाति की राजनीति नहीं करती। विद्यार्थी परिषद् अपने स्थापना-काल से राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हुए छात्रहित और राष्ट्रहित में अपना काम करती आ रही है। नज़ीब को जेएनयू के छात्र के तौर पर नहीं धर्म के नाम पर प्रदर्शित करके हिंदू-मुस्लिम दंगा कराना चाहते हैं।

अभाविप-नेताओं ने कहा कि छात्रसंघ उपाध्यक्ष ज़वाब दें कि वह देशद्रोही नारे लगानेवाले आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, जेएनयू में जब 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे नारे लग जाते हैं, तब एएमयू छात्रसंघ क्यों नही बोले? वह इसलिए कि वे एएमयू के छात्र हैं जो देशद्रोहियों को संरक्षण देते हैं। ऐसे ही लोगों से विद्यार्थी परिषद् की लड़ाई है। केरल और पश्चिम बंगाल में विद्यार्थी परिषद् और आरएसएस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोले? क्या वे इंसान नहीं हैं?

उन्होंने कहा कि एएमयू में ये जो भी गतिविधियाँ चल रही है, वे सब वामपंथियों की साजिश के तहत चल रही हैं। एआईएसएफ के सदस्य मोहित पाण्डे और मो. कासिम ने स्वयं बयान देकर हस्ताक्षर करके पहले नज़ीब को दोषी बताया, कासिम ने तो यहाँ तक कहा कि उसे नज़ीब से डर लगता है। अब ये अपने बयान से बदल रहे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नज़ीब को वामपंथियों द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए गायब करा देने की पूरी संभावना है। ज्ञात हो कि 09 फरवरी की देशद्रोही घटना के बाद अनिर्बान और उमर ख़ालिद भी गायब हो गए थे, फिर परिसर के अंदर ही मिले। अभाविप ने केन्द्र सरकार से मांग की है कि जेएनयू के सारे छात्रावासों व प्रोफेसरों के घरों की तलाशी ली जाए। नज़ीब संभवतः जेएनयू में ही होगा। ■

छात्र नेता सम्मेलन, रेवाड़ी

लक्ष्य के आगे गायब हो जाती हैं अड़चनें : एम.पी. गोयल

यदि इरादे मज़बूत हों तो इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। जीवन में लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें तो खुद-ब-खुद मंज़िल के आगे की अड़चनें गायब हो जाती हैं। हर समस्या के अंदर ही समाधान छिपा रहता है। उक्त बातें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा बावल रोड स्थित गार्डेन, रेवाड़ी में आयोजित छात्र-नेता सम्मेलन में **'समस्याओं से समाधान की ओर'** परिचर्चा में समाजसेवी एम.पी. गोयल ने कहीं।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के इतिहास और विकास पर प्रकाश डालते हुए अखिल भारतीय छात्रा प्रमुख ममता यादव ने कहा कि अभाविप अपने स्थापना काल से ही छात्रहित के लिए संघर्ष करती रही है। राष्ट्रहित के मसले को सबसे पहले उठाने का काम विद्यार्थी परिषद् ने किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, उस समय भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ बिगुल छात्रों ने फूँका था। शहीद-ए-आज़म भगत सिंह ने अपने छात्र जीवन में ही स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। हर आंदोलन में छात्रों की भूमिका अहम रही है। विद्यार्थी परिषद् ने 1990 के दशक में **'चलो कश्मीर'** रैली की थी और लाल चौक पर भारतीय ध्वज फहराने का आह्वान किया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया था। बाद में तत्कालीन जम्मू-काश्मीर सरकार ने अभाविप-कार्यकर्ताओं को लाल चौक पहुँचने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया।

बांग्लादेशी घुसपैठ के ख़िलाफ सबसे पहला मुहिम छेड़ने का काम अभाविप ने ही किया। भारत में घुसे हुए बांग्लादेशी-घुसपैठियों का सर्वेक्षण करने के बाद 2008 में **'चिकेन नेक'** में विशाल छात्र प्रदर्शन किया था और तत्कालीन गृहमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था। तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् ने पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठ की बात स्वीकार की थी।

अभाविप ने हमेशा समाज में परिवर्तन लाने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद् महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर में व्याप्त कमियों को रचनात्मक रूप से दूर करने का प्रयास करती है। परिषद् के कार्यकर्ता बेहद अनुशासित और सुसंस्कृत होते हैं। अभाविप छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करती है। आपलोग भी अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर की कमियों को रचनात्मक रूप से दूर करने का प्रयास करें।

बाद में हिसार ज़िले के महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र-नेताओं का मनोनयन (चुनाव) हुआ। यहाँ आए सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष व मंत्रियों से उसके परिसर में उपस्थित समस्याओं का ब्यौरा मांगा गया और उन मांगों को स्थानीय विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्षों की घोषणा प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप यादव द्वारा की गयी। इस अवसर पर केंद्रीय विवि के प्रांत संयोजक मनीष गुप्ता, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एड. रवीन्द्र गुर्जर, जोगेन्द्र सिंह, ज़िला प्रमुख महेश कांटीवाल, सह-संयोजक दिवाकर नमनवाल, चमनलाल आदि हज़ारों छात्र-छात्राएँ मौजूद थे। ■

दीनदयाल उपाध्याय
जन्मशताब्दी
1916-2016

ऐसे थे अपने

पं. दीनदयाल उपाध्याय (1916-1966) की कर्मठता व कर्तव्यपरायणता और अन्य दुर्लभ गुणों की चर्चा आज भी लोकमानस में विद्यमान है और हमें प्रेरणा दे सकती है। उनके द्वारा बताया गया एकात्म मानव दर्शन का सिद्धान्त आज विद्वानों के लिए जिज्ञासा व शोध का विषय बन गया है।

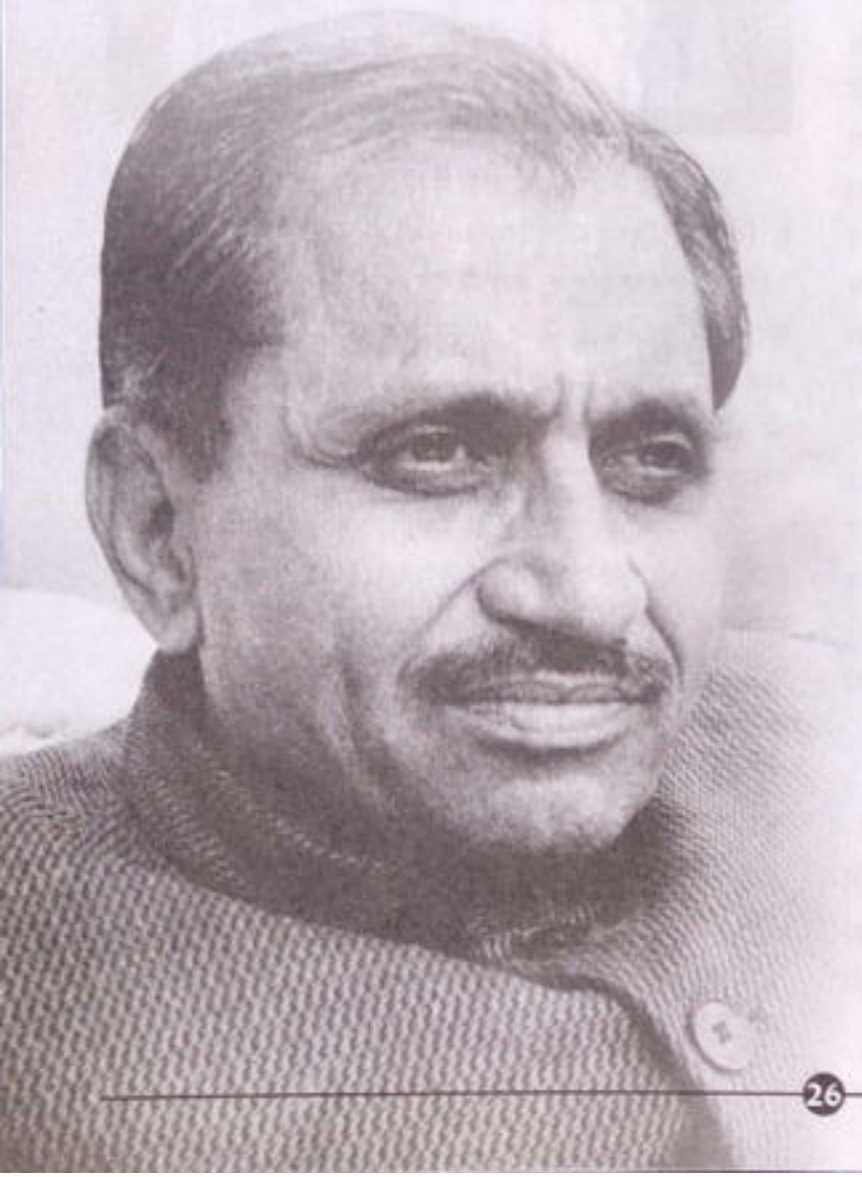

सुशील कुमार

यह रोचक घटना उस समय की है जब वे आगरा में एम.ए.(अंग्रेज़ी साहित्य) के छात्र थे। इस घटना से उनकी सरलता, सहजता एवं प्रामाणिकता प्रकट होती है। आज के युवा इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं।

चालीस-पचास साल पहले तक एक पैसे का सिक्का भी चलन में था। ये सिक्के तांबे के बने होते थे। एक बड़ा सिक्का, जिसमें काफी तांबा लगता था फिर उसमें एक गोल छेद करके उसका वजन कम किया गया। जो बड़ा और वजनजार सिक्का था, जिसे डबली या डबल पैसा भी कहा जाता था, वह जब घिस जाता था तो चलन के बाहर हो जाता था, दुकानदार उसे खोटा पैसा कहकर लौटा देते थे। यह सारा विवरण इसलिए कि पं. दीनदयाल उपाध्याय के छात्र-जीवन की एक घटना इस खोटे सिक्के से जुड़ी हुई है।

यह प्रसंग 1939 का है। उस समय दीनदयाल जी अंग्रेज़ी साहित्य विषय लेकर एम.ए.में पढ़ रहे थे। वे आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज़ के छात्र थे। अपने एक मित्र के साथ कमरा लेकर रहते थे, दोनों मिलकर खाना बनाते और खाते। ज़माना सस्ता था, सब्ज़ी खरीदने के लिए दो-तीन पैसे काफ़ी होते थे। सब्ज़ी बिक्री का भी एक अलग तरीक़ा था। बड़ी-बड़ी दुकानों पर सब्ज़ी नहीं बिकती थी। आगरा-जैसे बड़े शहर में भी कुछ ख़ास स्थानों पर पटरी

दीनदयाल जी

किनारे बोरी बिछाकर सब्जी बेचनेवाले बैठ जाते थे। टोकरी में सब्जी और बोरी के नीचे बिक्री के पैसे– यही चलन था। बेचनेवालों में महिला और पुरुष– दोनों होते थे और अच्छी आयु के ही अधिक होते थे।

एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों मित्र सब्जी खरीदकर परस्पर बातें करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि दीनदयाल जी अचानक असहज हो गए। उनके चेहरे पर चिन्ता के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वे चलते-चलते रुक भी गए थे। मित्र के पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी जेब में एक-एक पैसे के कुल तीन सिक्के थे और उसमें एक घिसा हुआ खोटा सिक्का था। जिन अम्मा से हमने दो पैसे की सब्जी खरीदी, उन्हें वह खोटा सिक्का दे आया हूँ। उस गरीब माँ का नुकसान हो गया और मुझे पाप लगेगा सो अलग। मित्र ने यह समझाने की कोशिश भी की कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम इतनी चिन्ता करो। जैसे तुम्हारा वह सिक्का चल गया, वैसे ही उसका भी किसी ग्राहक के पास चला जाएगा। पर दीनदयाल जी थे कि उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वे वापस बाजार गए और सब्जी बेचनेवाली माँ से सारी बात बतायी। दुकानदार माँ ने उसे माफ़ करते हुए कहा, 'बेटा! अब जैसा किसी के भाग्य में हानि लाभ लिखा होता है-वैसा ही होता है। तुम जाओ, तुम अपनी शुद्ध भावना के कारण खूब तरक्की करोगे।' पर दीनदयाल जी नहीं माने। तीसरा खरा सिक्का देकर और रेज़गारी के ढेर में से अपना खोटा सिक्का खोजकर ही माने। इसके बाद दीनदयाल जी के चेहरे पर उभरे संतोष को कोई भी देख सकता था।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर नियमित जानेवाले यही दीनदयाल जी आगे चलकर एक महान् दार्शनिक, लेखक और राजनीति में समाज के मार्गदर्शक व नेतृत्व सम्भालनेवाले बने। सन् 1967 में उनको भारतीय जनसंघ का अखिल भारतीय अध्यक्ष बनाया गया। उनकी कर्मठता व कर्तव्यपरायणता और अन्य दुर्लभ गुणों की चर्चा आज भी लोकमानस में विद्यमान है और हमें प्रेरणा दे सकती है। उनके द्वारा बताया गया एकात्म मानव दर्शन का सिद्धान्त आज विद्वानों के लिए जिज्ञासा व शोध का विषय बन गया है। ■

तीन तलाक : मुस्लिम महिला पर कहर

भारत में क्रिमिनल प्रोसिजर कोड लागू है, जो एक समान प्रकृति का है और जाति, लिंग, धर्म पर विचार किए बिना सभी नागरिकों पर यह लागू है। लेकिन इसी के साथ हमारे पास सिविल प्रोसिजर कोड है, जो विभिन्न धर्मों के लिए भिन्न-भिन्न है। यह विसंगति हटाई जानी चाहिए ताकि देश वास्तविक अर्थों में पंथनिरपेक्ष बन सके।

एड. मोनिका अरोरा

इतिहास

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत की मुस्लिम महिलाओं का है यह क्रंदन, जिन्हें आज भी बुनियादी अधिकारों से वंचना का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों जब हर कोई आज़ादी के लिए बेताब है, हमारी मुस्लिम बहनें भी आज़ादी चाहती हैं– तीन बार तलाक कहे जाने से, चार पत्नियोंवाले शौहर के उत्पीड़न से, हलाला वगैरह से।

तिहत्तर साल की एक बुज़ुर्ग महिला ने न्याय का दरवाजा खटखटाया ताकि बुढ़ापे में अपने गुजर-बसर के लिए कुछ सौ रुपये का गुजारा भत्ता पा सके। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह अदालत का दरवाजा खटखटाना भारत की राजनीति में तूफ़ान ला देगा। कभी नहीं सोचा था कि भोजन, कपड़े, आवास और दवाएँ मुहैया कराए जाने की उसकी फ़रियाद भारत में पर्सनल लॉ की बुनियाद ही हिला डालेगी। एक समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा नये सिरे से छिड़ जाएगी। आभारी हैं शाहबानो मामले के।

मो. अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम एवं अन्य (1985) 2 एससीसी 556

मो. अहमद खान एक सफल वकील और शाहबानो के शौहर थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा अपने खिलाफ दिए गए एक फ़ैसले के खिलाफ माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपील की थी। मजिस्ट्रेट ने अपने फ़ैसले में उन्हें उसकी बीवी शाहबानो को हर महीने 179 रुपये देने का निर्देश दिया था। साथ ही, व्यवस्था दी थी कि इस मूल राशि में प्रति माह 25 रुपये का इज़ाफा होगा। इस दंपत्ति की शादी 43 साल पहले हुई थी। बीमार और उम्रदराज़ होने पर शौहर ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। शौहर अपनी बीवी को प्रति माह 200 रुपये गुजारा भत्ता देता था। जब यह भुगतान रोक दिया गया तो पत्नी ने 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया।

माननीय न्यायालय के समक्ष सवाल था कि क्या कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रेसिजर, 1973 की धारा 125 इस मामले में लागू है? अदालत ने शाहबानो के पक्ष में फ़ैसला दिया। अदालत ने यह भी सिफ़ारिश की कि एक समान नागरिक संहिता तैयार की जानी चाहिए।

राजनीतिक प्रभाव-प्रतिक्रियाएँ

शाहबानो राष्ट्रव्यापी राजनैतिक मुद्दा बन गयी। हर कहीं उसके मामले को लेकर विवादास्पद बहसें चल पड़ीं। आपराधिक अदालत को मुस्लिम पर्सनल लॉ के खतरे के रूप में देखा जाने लगा। उन्हें हिंदू दबदबे और हिंदू-मूल्यों को थोपे जाने का संकेत समझा जाने लगा। राजीव गाँधी के नेतृत्व में काँग्रेस सरकार, जिसने शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले का समर्थन किया था, दिसम्बर, 1985 में स्थानीय चुनाव में शिकस्त खा बैठी।

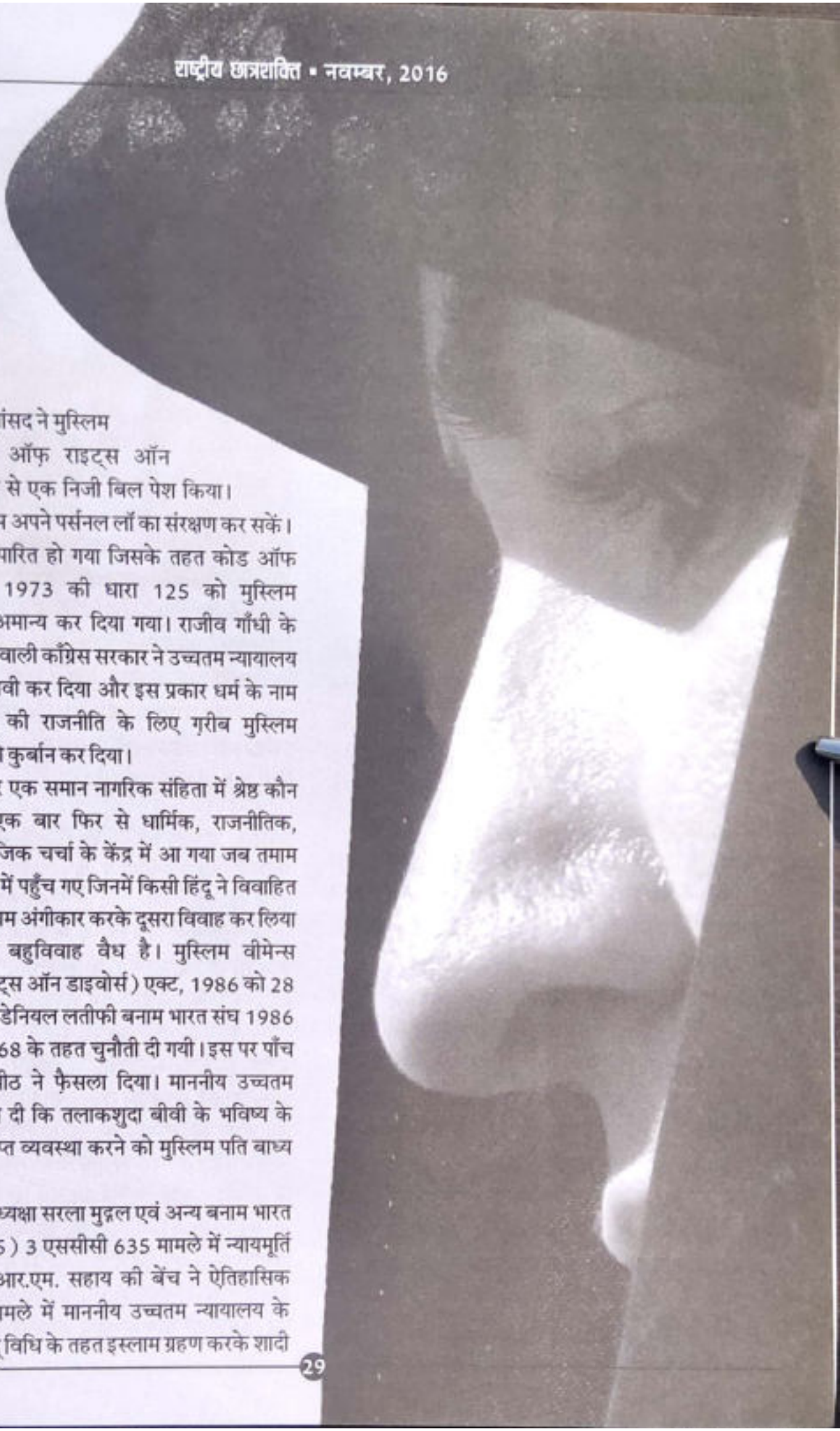

मुस्लिम वीमेन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986

एक मुस्लिम महिला सांसद ने मुस्लिम वीमेन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन डाइवोर्स) बिल, नाम से एक निजी बिल पेश किया। इस मंशा से कि मुस्लिम अपने पर्सनल लॉ का संरक्षण कर सकें। यह बिल 1986 में पारित हो गया जिसके तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रेसिजर, 1973 की धारा 125 को मुस्लिम महिलाओं के लिए अमान्य कर दिया गया। राजीव गाँधी के नेतृत्व में निष्ठुर बहुमतवाली कॉंग्रेस सरकार ने उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले को निष्प्रभावी कर दिया और इस प्रकार धर्म के नाम पर और वोट बैंक की राजनीति के लिए ग़रीब मुस्लिम महिलाओं के हितों को कुर्बान कर दिया।

पर्सनल लॉ और एक समान नागरिक संहिता में श्रेष्ठ कौन को लेकर विवाद एक बार फिर से धार्मिक, राजनीतिक, वैधानिक और सामाजिक चर्चा के केंद्र में आ गया जब तमाम ऐसे मामले अदालतों में पहुँच गए जिनमें किसी हिंदू ने विवाहित होने के बावजूद इस्लाम अंगीकार करके दूसरा विवाह कर लिया क्योंकि इस्लाम में बहुविवाह वैध है। मुस्लिम वीमेन्स (प्रोटेक्शन ऑफ़ राइट्स ऑन डाइवोर्स) एक्ट, 1986 को 28 सितम्बर, 2001 को डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ 1986 के डब्ल्यूपी (सी) 868 के तहत चुनौती दी गयी। इस पर पाँच सदस्यीय संविधान पीठ ने फ़ैसला दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि तलाकशुदा बीवी के भविष्य के लिए उचित और पर्याप्त व्यवस्था करने को मुस्लिम पति बाध्य है।

कल्याणी की अध्यक्षा सरला मुद्गल एवं अन्य बनाम भारत संघ (10 मई, 1995) 3 एससीसी 635 मामले में न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह और आर.एम. सहाय की बेंच ने ऐतिहासिक फ़ैसला दिया। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने मुद्दा था कि हिंदू विधि के तहत इस्लाम ग्रहण करके शादी

करनेवाला मुस्लिम बना व्यक्ति क्या दूसरी शादी कर सकता है ? उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इस्लाम अंगीकार करने के बावजूद कोई हिंदू पहली शादी को इसी क़ानून के तहत समाप्त किए बिना ऐसा नहीं कर सकता।

हिंदू कोड बिल और निर्देशक सिद्धांतों का परिशिष्ट

भारतीय संसद ने हिंदू लॉ कमेटी की सिफारिशों पर 1948-1951 तथा 1951-54 के सत्रों के दौरान चर्चा की थी। खासे शोर-शराबे और विवाद के उपरांत संसद ने 1956 में चार पृथक अधिनियम पारित किए गए। ये थे : हिंदू मैरिज एक्ट; हिंदू सक्सेजन एक्ट; हिंदू माइनॉरिटी एण्ड गार्डियनशिप एक्ट तथा हिंदू अडोप्शन एंड मैंटिनेंस एक्ट। अलबत्ता, एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं करवाई जा सकी।

स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954

स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत व्यवस्था है कि कोई भी नागरिक धर्म विशेष से इतर विवाह कर सकता है। इस प्रकार कोई भी भारतीय किसी धर्म विशेष के पर्सनल लॉ से इतर विवाह कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू तथा मुस्लिमों, सिख तथा ईसाइयों को विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई है।

गोवा यूनिफॉर्म सिविल कोड

गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जो इसके निवासियों पर लागू होता है। गोवा का विलय भारतीय संघ में 1961 में हुआ था। गोवा ने अपनी नागरिक संहिता साथ बनाए रखी जिसके तहत बहुविवाह अपराध होता है। यहाँ तक कि उन मुस्लिम महिलाओं, जिनकी शादी गोवा में पंजीकृत हैं, को तीन बार 'तलाक तलाक तलाक' बोलकर तलाक नहीं दिया जा सकता। सभी विवाह अनिवार्यतः पंजीकृत होते हैं।

लिली थॉमस एवं अन्य बनाम भारत संघ (2000) 6 एससीसी 224

लिली थॉमस एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने कहा था कि यदि नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की संवैधानिक अनिवार्यता के रूप में व्यवस्था होती तो शाहबानो तथा सरला मुद्गल-जैसे मामले सामने आते ही नहीं।

निष्कर्ष

नागरिक संहिता में विवाह, विवाह-विच्छेद, गुजारा-भत्ता, विरासत, उत्तराधिकार वगैरह से जुड़े क़ानून शामिल होते हैं। भारत में क्रिमिनल प्रोसिजर कोड लागू है, जो एक समान प्रकृति का है और जाति, लिंग, धर्म पर विचार किए बिना सभी नागरिकों पर यह लागू है। लेकिन इसी के साथ हमारे पास सिविल प्रोसिजर कोड है, जो विभिन्न धर्मों के लिए भिन्न-भिन्न है। यह विसंगति हटाई जानी चाहिए ताकि देश वास्तविक अर्थों में पंथनिरपेक्ष बन सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 देश के प्रत्येक नागरिक को क़ानून की दृष्टि में समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। सभी को क़ानून का संरक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही, सभी को सम्मान के साथ जीवन सुनिश्चित करने का अधिकार देते हैं। संभव है कि किसी रोज कोई बुद्धिजीवी, कोई शिक्षाविद्, कोई एनजीओ, कोई मीडियाकर्मी, कोई मानवाधिकार संगठन, जेएनयू का कोई छात्र या कोई अन्य विश्वविद्यालय मुस्लिम महिलाओं को उनके अमानवीय जीवन और हालात से निजात दिलाने के लिए यह आह्वान कर दे। कह उठे : हम लेकर रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। ■

संभव है कि किसी रोज कोई बुद्धिजीवी, कोई शिक्षाविद्, कोई एनजीओ, कोई मीडियाकर्मी, कोई मानवाधिकार संगठन, जेएनयू का कोई छात्र या कोई अन्य विश्वविद्यालय मुस्लिम महिलाओं को उनके अमानवीय जीवन और हालात से निजात दिलाने के लिए यह आह्वान कर दे।

परिचर्चा

पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम देने का औचित्य ?

विगत 18 सितम्बर को आतंकवादियों के द्वारा उरी में जवानों के शिविर पर हमला किया गया, जिसमें हमारे देश के 19 जवान शहीद हो गये। इस घटना के बाद पाकिस्तान के खिलाफ देशवासियों में गुस्सा व्याप्त है। बाद में भारतीय सेना के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक करके गुलाम काश्मीर के अंदर जाकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया। इसमें 39 आतंकवादी सहित कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गये। इसके बाद भी भारतीय जनमानस का गुस्सा थम नहीं रहा है। देशवासियों की मांग है कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अभी हाल ही में एक फ़िल्म प्रदर्शित हुई है जिसमें पाकिस्तानी कलाकार ने काम किया है, जिसका देशभर में विरोध भी हुआ। कुछ लोग पाकिस्तानी कलाकार के समर्थन में है तो कुछ विरोध में। पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगना चाहिये या नहीं इसको लेकर 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' के लिए अमीत कुमार सिंह ने देशभर के छात्रों से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के अंश...

पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में काम करने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगना चाहिए। पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार से लगातार घुसपैठ का प्रयास करके हमारे देश को अशांत और अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी कलाकारों का

भारत में काम करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है।

–प्रखर मिश्र, रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)

पाकिस्तान भारत का जन्मजात शत्रु है। वह रोज किसी-न-किसी प्रकार से हमारे देश को हानि पहुँचाने का काम कर रहा है। दुश्मन देश का नागरिक प्रायः दुश्मन ही होता है। मेरे विचार से पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बिल्कुल काम करने की इज़ाज़त नहीं देनी चाहिए। इनलोगों को भारत में इतना सम्मान और प्यार मिलता है और फिर बाद में यही लोग हमारे देश को बदनाम करने का काम करते हैं। इनलोगों का पैसा पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तानी सरकार उस पैसे से आंतकवादियों को बढ़ावा देने का काम करती है। आतंकवादियों के द्वारा हमारे सैनिक भाइयों पर गोली चलाई जाती है। एक तरफ हमारे देश में पाकिस्तान के प्रति कड़ा आक्रोश है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को काम देना सरासर गलत है। पाकिस्तानी कलाकारों को अपने देश में काम देना शहीदों का अपमान है।

–अभिनव, जम्मू विश्वविद्यालय (जम्मू-काश्मीर)

पाकिस्तानी कलाकार हमारे देश में आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भारत का कोई भी कलाकार या नागरिक यदि पाकिस्तान जाता है तो वहाँ उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमलोग जिस तरह से अपने देश में पाकिस्तानी कलाकारों या वहाँ के नागरिकों को प्यार-सम्मान देते हैं, उस तरह वे लोग कभी नहीं देते। पाकिस्तानी कलाकारों में यदि प्रतिभा है तो वे अपने देश में दिखायें, हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं। पाकिस्तान के अलावा दूसरे देश के कलाकारों को भी हमारे देश में कला दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में भारत-पाकिस्तान का रिश्ता ठीक नहीं है। पाकिस्तान के द्वारा रोज हमारे जवानों को निशाना बनाया जाता है। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तानी कलाकारों का भारत में प्रतिबंध लगना जायज है।

–पूजा कुमारी, जी.डी. खालसा कॉलेज़, दिल्ली विश्वविद्यालय

हमारे देश में कलाकारों की कमी नहीं है। अपने देश के कलाकारों को बढ़ावा देना चाहिए। पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम नहीं करने दिया जाना चाहिए। ये लोग खाते भारत का हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। यहाँ आकर ये कमाते हैं और फिर भारत को बदनामी करते हैं। इनलोगों पर भरोसा किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता है। इनलोगों ने हमारे देश की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। उरी में हमारे 19 जवान शहीद हुए, मानवता के नाते भी इनलोगों ने एकबार भी जवानों के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की और न ही आतंकियो के इस कृत्य का निन्दा की। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने की पाबन्दी लगना समय की मांग है।

–अधिन, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, केरल

पाकिस्तानी कलाकारों का हमारे देश में काम करना सौ फीसदी बंद होना चाहिए। पाकिस्तानी कलाकार भारत से धन कमाकर जाते हैं और पाकिस्तान सरकार को टैक्स अदा करते हैं। पाकिस्तानी सरकार उस पैसे से गोली बनाती है, जो बाद में हमारे सैनिकों पर दागी जाती है। हम अपने पैसों से अपने ही भाइयों को मौत के घाट नहीं उतार सकते। पाकिस्तानी कलाकार ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से आनेवाली हर चीज पर पूरी तरह भारत में प्रतिबंध लगना चाहिए और इसके साथ-साथ चीनी सामानों का भी पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। इस बार दीवाली में चीनी सामानों के बहिष्कार करने की जो मुहिम चलाई गई, वो काफ़ी हद तक सफल भी रही। चीन हमारे पैसे से गोली बनाता है और उस गोली को पाकिस्तान के पास बेचता है। फिर घूमकर वे गोलियाँ हमारे जवानों

पर दागी जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान और पाकिस्तान-समर्थक देश द्वारा निर्मित वस्तुओं पर ज़रूर प्रतिबंध लगना चाहिए।

–राणा नौशाद मलूक, दिल्ली विश्वविद्यालय

कला-संस्कृति को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। कला एक देश की संस्कृति को दूसरे देश में ले जाने का काम करती है, जिससे एक-दूसरे देश की संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। लेकिन मौजूदा हालात में यह सब राजनीति की भेंट चढ़ गया है। हिंसा या आतंकवाद को किसी भी रूप नहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, यह सही है कि पाकिस्तान के द्वारा लगातार हमारे देश में आतंक फैलाने का काम किया जाता है, लेकिन इन कलाकरों का उसमें क्या दोष है? लेकिन इन कलाकारों का भी कर्तव्य है कि जिस देश का नमक खाए, उस देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान संवाद के जरिये किया जाता है। यदि आप संवाद ही बंद कर देंगे तो समस्या का निदान कहाँ से होगा।

–जी. गणेशपूनम, चेन्नई (तमिलनाडु)

एक तरफ पाकिस्तान हमारे देश के जवानों पर गोली बरसाता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने देना घोर नाइंसाफी है। पाकिस्तानी कलाकारों को ऐसे लोग समर्थन दे रहे हैं जिनके परिवारजनों को भारत में असहिष्णुता दिखाई देती है। ये लोग खाते तो भारत के हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। पाकिस्तानी कलाकार कभी भी भारत का हित नहीं सोच सकते। अगर उन्हें जरा सी भी हमदर्दी होती तो उड़ी-हमले के शहीदों के प्रति ज़रूर संवेदना व्यक्त करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तानी कलाकारों को काम देने के बजाय अपने देश के नये कलाकारों को मौका दिया जाना चाहिए, यही देश और समाज के लिए हितकर होगा।

–अनीमा सोनकर, छात्रा (एम. फिल्.) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली

पाकिस्तानी कलाकार भारत में आकर कमाते हैं और पाकिस्तान में जाकर इस पैसे का उपयोग करते हैं। जिसका कुछ हिस्सा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वहाँ के हुक्मरान को भी जाता है और वहाँ के हुक्मरान सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवादियों को भारत भेजने का काम करते हैं। आतंकवादियों के द्वारा हमारे देश में हिंसा फैलाने का काम किया जाता है। आतंकवादियों के द्वारा ख़ासकर हमारे सुरक्षाबलों को निशाना बनाया जाता है। हम अपने पैसों से अपने ही जवानों पर गोली चलानेवालों को काम करने की इज़ाज़त नहीं दे सकते।

–विंकल शर्मा, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी (पंजाब)

संस्कृति और कला को राष्ट्र से अलग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्र के स्वाभिमान को ताक पर रखकर दूसरे देश के कलाकारों को बढ़ावा देना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के लिए आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर हमला करवाता है। ऐसी हालत में यदि पाकिस्तान से या पाकिस्तानी कलाकार नागरिकों से किसी भी तरह संबध रखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि सीमापार आतंकवाद को लेकर हम ज़्यादा गंभीर नहीं हैं। पाकिस्तानी नागरिक का जो नेतृत्व करता है, वही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। सीमा पर लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम देना एक आत्मघाती कदम होगा।

–एन. सुशील कुमार, हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय

■

हुंकार रैली से छात्रों की ताकत का एहसास करायेगा विद्यार्थी परिषद्

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् 23 नवम्बर को राजधानी लखनऊ में प्रदेश की लचर शिक्षा-व्यवस्था के खिलाफ 'छात्र हुंकार रैली' का आयोजन कर रहा है। रैली को लेकर तैयारी जोरों पर है। इसके लिए अभाविप-कार्यकर्ता पूरे प्रदेशभर में जगह-जगह जनजागरण यात्रा निकाल रहे हैं। इस रैली के माध्यम से विद्यार्थी परिषद् कुंभकर्णी निंद्रा में सोई अखिलेश सरकार को छात्रों की ताकत का एहसास कराने का प्रयास करेगा।

अभाविप की यह हुंकार रैली राजधानी के कॉल्विन तालुकेदार महाविद्यालय परिसर में प्रस्तावित है। इसमें प्रदेशभर के एक लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने की योजना है। विद्यार्थी परिषद् इस तरह का आयोजन करीब 22 साल बाद कर रही है। इससे पहले 1994 में ऐसी रैली का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग 64 हजार छात्रों ने भाग लिया था।

विद्यार्थी परिषद् के क्षेत्रीय संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह बताते हैं कि 23 नवम्बर को होनेवाली रैली में प्रदेशभर से एक लाख छात्रों के आने की सम्भावना है। इसके लिए लोगों से घर-घर जाकर सम्पर्क किया जा रहा है। पदयात्राएँ निकाली जा रही हैं। बाइक रैली के माध्यम से छात्रों के आने का आह्वान किया जा रहा है। कोशिश है कि रैली में ज़्यादा-से-ज़्यादा छात्र शामिल होकर अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठा सकें।

उन्होंने बताया कि विद्यार्थी परिषद् अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। प्रदेश की वर्तमान सरकार को कई बार आंदोलनों और ज्ञापनों के जरिए शिक्षा और शिक्षण संस्थाओं की स्थिति ठीक करने की चेतावनी भी दी गयी, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से उस पर कुछ नहीं हुआ। शिक्षा की अव्यवस्था को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन उस तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।

बाइक रैली के माध्यम से छात्रों को जोड़ने की कवायद

तेईस नवम्बर को लखनऊ में प्रस्तावित छात्र हुंकार रैली की सफलता के लिए अभाविप कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में बाइक रैली निकालकर छात्र-छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं। इस दौरान संगठन के पदाधिकारी छात्र हित की आवाज बुलंद करते हुए प्रदेश में शिक्षा-व्यवस्था को पूरी तरह से पटरी से उतरने का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं।

क्या है मांग ?

शिक्षण-संस्थाओं में 180 दिन पढ़ाई कराई जाये। शैक्षिक सत्र नियमित हों। छात्रसंघ के चुनाव कराए जायें। रिक्तपदों पर शिक्षकों की तत्काल तैनाती हो। इंटरमीडिएट स्तर तक छात्र-छात्राओं की शिक्षा निःशुल्क हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाये। इसके अलावा विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में महिला-प्रकोष्ठ की स्थापना समेत अनेक मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद् अपने आंदोलन को धार देने लगी है। ■

परिषद्-गतिविधियाँ

रेवाड़ी में छात्र नेता सम्मेलन

हिसार में छात्र महापंचायत

कर्नाटक में छात्रा-सम्मेलन का उद्घाटन करते अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनय बिदरे

RNI 32464/78

जितनी ऊँची वज़न की रेखा उतना अच्छा बच्चा देखा

- पाँच साल तक के सभी बच्चों का नजदीकी आँगनवाड़ी केन्द्र पर प्रति माह नि:शुल्क वज़न करायें और बच्चे का वृद्धि कार्ड बनवायें।
- इससे आप उसकी वृद्धि और विकास की निगरानी कर सकते हैं।
- नियमित वृद्धि निगरानी से बच्चे के पोषण स्तर के बारे में सही जानकारी मिलेगी और उसे स्वस्थ रखा जा सकता है।
- बच्चे की वृद्धि सामान्य है या कम, इसकी पहचान कर वृद्धि को सुधारने के समय रहते प्रयास किये जा सकेंगे।
- ऐसा करने से बच्चे को बीमारी या कुपोषित होने से भी बचाया जा सकता है।

श्री शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

बच्चे के वजन में मासिक वृद्धि

उम्र	वजन में मासिक वृद्धि
जन्म से 6 माह	600 से 800 ग्राम
7 माह से 12 माह	300 से 400 ग्राम
1 वर्ष से 3 वर्ष	150 से 200 ग्राम
3 वर्ष से 5 वर्ष	125 ग्राम

विशेष वजन अभियान

1 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2016 तक

अपने बच्चे का वजन अवश्य करायें

http://www.mpwcd.nic.in
http://mpwcdmis.gov.in
http://esanchayika.in
https://www.facebook.com/ICDSMP

संचालनालय एकीकृत बाल विकास सेवा
महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश